[Mr. Deputy Speaker]

R. K. Khadilkar, Shri P. Kunhan, Shri Lahri Singh, Shri Lalit Sen, Shri Inder J. Malhotra, Shri T. Manaen, Shri Jaswantraj Mehta, Shri Bakar Ali Mirza, Shri Bibudhendra Misra, Shri Mohan Nayak, Shri Ghanshyamlal Oza, Shri R. S. Pandey, Shri Ram Singh, Shri Hari Charan Soy, Shri M. P. Swamy, Shri Krishna Deo Tripathi, Shri Tula Ram, Shri Ram Sewak Yadav, Shri Bhisma Prasad Yadava and Shri Asoke K. Sen with instructions to report by the last day of the first week of the next session."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up the discussion on matter of urgent public importance. Shri Bishanchander Seth.

DISCUSSION *RE.* BREAKDOWN OF POWER SUPPLY IN DELHI

श्री बिशनचंद्र सेठ (एटा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी के सम्बन्ध में बहुत समय से हमारे सदन में अनेक प्रकार की बातें आती रही हैं और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि सरकार के सामने समय समय पर अनेक प्रकार के सुझाव रखे गए और जो कष्ट जनता के थे वे भी सामने लाए गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी केन्द्रीय सरकार, देश की राजधानी जैसे महत्वपूर्ण स्थान में भी आज बिजली और पानी जैसी जीवन की दैनिक आवश्यकताओं का उचित प्रबन्ध नहीं कर पा

मैं कभी कभी यह सोचने लगता हूं कि सामान्य जीवन के दिनों में, जब कि हमारे देश के सामने कोई भी महत्वपूर्ण समस्या नहीं है, हमारा देश सामान्य स्थिति में चल रहा है, पानी और बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय का हमारी सरकार प्रबन्ध करने में अपनी असमर्थता अनुभव कर रही है। ईश्वर न करे कि देश के सामने कोई महत्वपूर्ण क्लेश आ जाए, तब हमारी क्या स्थिति होगी यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इसे सोच कर मेरे दिमाग में बड़ी उलझन और परेशानी पैदा होती है।

मैं आपसे बताना चाहता हूं

14.59 hrs.

[MR. SPEAKER *in the chair*]

कि आज से कुछ दिन पहले समाचारपत्रों में छपा था, उसी का रेफ़रेंस देना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट के लिए आप मुझे इजाज़त दें सेठ साहब तो बेहतर होगा। इस बहस में बहुत से माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कोई टाइम लिमिट मुकर्रर कर दी जाए तो अच्छा होगा। आप को मूव करने के लिए १५ मिनट काफ़ी होंगे ?

श्री बिशनचंद्र सेठ : मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस पर ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इत्तला मिली है कि काफ़ी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कौन साहब इस में हिस्सा लेना चाहते हैं ?

(कुछ माननीय सदस्य अपनी जगहों पर खड़े हुए)

९ या दस हो गये और मुमकिन है शायद एक आध और कोई आ जाये इसलिए आप २० मिनट ले लीजिए और बाकी माननीय सदस्य १५ मिनट का समय लें।

श्री बिशनचंद्र सेठ : ठीक है जैसी आप की आज्ञा।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : जैसा आप ने कहा है वैसा ही होगा ।

बिशनचन्द्र सेठ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि पहली अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी थी कि दिल्ली कारपोरेशन की मीटिंग में बिजली के जनरल मैनेजर ने इस बात को खास तरीके से पेश किया कि हमारे जेनेरेटर्स इतने पुराने हो गये हैं कि जितनी ताकत उन के जरिये से बननी चाहिये वह नहीं बन रही है । अगर उन को चलाया गया तो वह और रिस्की हो जायेंगे और अगर जरा ओवरलोड किया गया तो और भी ज्यादा दिक्कत आयेगी । इसी के साथ साथ ५ अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स में पुनः इसी चीज के सम्बन्ध, में एक बड़ा लम्बा चौड़ा स्टेटमेंट निकला । मैं आप को यहां पर यह बतलाना चाहता हूं कि ५ तारीख वाली सूचना में एक बड़े मजाक की बात कही गई है । उस में दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी वालों ने अपने सारे चार्जेज, पंजाब वालों पर डाले हैं और उन्हों ने कहा है कि इस के लिये खतावार पंजाब की इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है । दूसरी ओर पंजाब वालों ने इस के लिये सारा का सारा उत्तरदायित्व दिल्ली वालों पर डाला है । यह कन्फयूजन हमारे सामने है ।

दिल्ली जोकि हमारे देश की राजधानी है और जहां कि विभिन्न देशों के राजदूत रहते हैं वहां का सारा प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये जिस पर गर्व किया जा सके क्योंकि केन्द्र की राजधानी होने को खातिर दिल्ली की ओर सब की नजर रहती है । दिल्ली में अनेकों देशों के बड़े बड़े लोग आया करते हैं और सामान्य जीवन की आवश्यकतायें जैसे पानी और बिजली आदि का भी जब हम समुचित प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं तो उस का उन सभी पर एक खराब असर पड़ता है और वह हमारे देश के बारे में कोई अच्छी राये कायम नहीं कर सकते हैं ।

मैं इसी के सम्बन्ध में आप से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जो स्टेटमेंट आज टेबुल पर रक्खा गया उस में स्पष्ट अंकित है कि अक्तूबर १९६१ में सब स्टेशन फेल हुआ था । उस में यह लिखा है कि जो जेनेरेटर या जो मशीन फेल हुई उस की नार्मल लाइफ ३५ साल की थी परन्तु वह सात वर्ष के अन्दर दो बार फेल हुए । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब अक्तूबर सन् १९६१ में यह चीज केन्द्रीय सरकार के समक्ष लाई गई और आज उस बात को दस महीने होने को आये तो क्या हमारे देश के शासन प्रबन्ध में इतनी अधिक ढिलाई है कि एक बात और एक समाचार जोकि केन्द्रीय नगर में बिजली की इतनी बड़ी समस्या पैदा कर रहा है उस को सफलतापूर्वक हल करने के लिये इस दस महीने की लम्बी अवधि में भी कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ ? अगर इसी प्रकार की परिस्थिति हमारे देश में बनी रही तो कैसे हम लोगों के हृदय में यह विश्वास पैदा होगा कि हम किसी भी प्राबलम को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे ? जबकि हम जीवन की दो महत्वपूर्ण आवश्यकतायें बिजली और पानी का भी समुचित प्रबन्ध करने में असफल रहते हैं तो इस का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव देश की जनता पर पड़ने वाला है और उस को हमारी क्षमता में कोई भी विश्वास नहीं रह जायेगा ।

मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि अखबारों में कलकत्ते में बिजली की शौर्टेज के सम्बन्ध में काफी छप रहा है । मैं अभी चंद दिन पहले मथुरा और आगरा गया था । मथुरा जैसा बड़ा नगर जहां कि आजकल श्रावण के दिनों में लाखों आदमी देश के विभिन्न भागों से वहां पर नित्यप्रति पहुंचते हैं बिजली की स्थिति यह है कि किसी भी आदमी को यह मालूम नहीं कि बिजली किस समय और कितनी देर के लिये चली जायेगी ? दो रोज मथुरा रहने

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

के बाद मैं आगरा गया । वही मथुरा वाला किस्सा आगरा में भी मैं ने देखा । अब अगर मैं अपने नगर शाहजहांपुर की बात कहूं तो वहां तो हालत यह है कि यह पता ही नहीं रहता कि बिजली आयेगी अथवा नहीं या आज शाम को बिजली आयेगी या गुल रहेगी । सारे देश में यह बिजली की प्राबलम है लेकिन तो भी खेद का विषय है कि हम अपने देश की इस महत्वपूर्ण दैनिक आवश्यकता के सम्बन्ध में कितने उदासीन हैं । इस को हल करने के लिये हमारे सामने कोई मशीनें नहीं आती । नये नये प्रकार के रोज प्रोजेक्ट बनते हैं और अनेकों वर्ष से दुनिया भर में उस की चर्चा चल रही थी कि हम अपने देश में एक ऐसी मोटर कार बनाने जा रहे हैं जिस को सामान्य स्थिति के लोग इस्तेमाल कर सकेंगे परन्तु आज पता लगा कि वह सारी की सारी भावनायें शैल्व कर दी गई । अनेक कारण हैं उन कारणों की ओर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार के प्रति देश की जनता के मन में विश्वास की लहर तभी पैदा हो सकती है जबकि हम जो भी निर्णय करें जो भी चीज सरकार की ओर से समाचारपत्रों में प्रकाशित हो उस को पूरा किया जाये। आज हमारे देश की जैसी स्थिति हो रही है उस में एक निर्णय करने के बाद पता नहीं लगता है कि कल को उस का क्या परिवर्तित रूप आयेगा ।

मैं ने आगरा और शाहजहांपुर के सम्बन्ध में इसलिये चर्चा कर दी कि मैं अभी चार दिन पहले वहां गया था । इन के अलावा अनेक अन्य शहर जहां भी मैं गया हूं वहां पर कहीं भी मैं ने बिजली की संतोषजनक व्यवस्था नहीं देखी । करीब करीब सारे देश में यह परिस्थिति है और कहीं भी लोगों को इस का विश्वास नहीं है कि उन की बिजली बराबर कायम रहेगी । यह परिस्थिति कब से आई मैं इस का एक विशेष उल्लेख आप की सेवा में करना चाहता हूं । जब से हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारे देश में आई हमें यह पता नहीं लगता कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक कब बन्द हो जायेगी । एक रेंज के बन्द होने से केवल एक नगर की ही बिजली नहीं बन्द होती बल्कि उस रेंज में जितने भी नगर पड़ते हैं सब में बिजली गुल हो जाती है ।

मैं अपने नगर शाहजहांपुर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । शाहजहांपुर, पीलीभीत और बरेली

अध्यक्ष महोदय बहुत जोर आप शाहजहांपुर पर न दें बल्कि दिल्ली के बारे में कहें ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : श्रीमान्, मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूं और वहीं पर अपनी शेष उम्र भी व्यतीत करनी है । अब यह तो संयोग की बात है कि लोकसभा में चुन कर कुछ समय के लिये मैं दिल्ली में आ गया हूं

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो मोशन दिया है वह दिल्ली के बारे में है ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं उसी के बारे में अर्ज कर रहा हूं । मैं अन्य नगरों की बाबत इसलिये चर्चा कर रहा था कि वहां पर भी यह बिजली का संकट है और इसलिये वह भी इस से सम्बन्धित होते हैं । सारे देश में यह बिजली का संकट मौजूद है । मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता लेकिन केवल मैं यह बतलाना चाहता था कि आज एक्चुएली पोजीशन क्या है ?

खैर मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि एक सरकिट जब खराब होता है तो केवल एक नगर की ही नहीं बल्कि उस सर्किट के अन्तर्गत जितनी भी ८, १२ या

१५ नगर पड़ते हैं उन सब में बिजली ठप्प हो जाती है। दैनिक जीवन की आवश्यकतायें जिन का कि सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है जनता को वह आवश्यक सुविधायें जब सुलभ नहीं हो पातीं साथ ही उन को हल करने की ओर जो सरकार की उदासीनता बरती जाती है तो इस का बाहर के देशों पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में जिस में एक ओर चीन हमारे सिर पर सवार है और दूसरी ओर पाकिस्तान जिस तरह से हमारी ओर शत्रुता भरी आंख से ताक रहा है वह हम सब को पता है। क्या हमारी इन कमजोरियों को देखने के बाद हमारे पड़ोसी राज्य यह नहीं सोचेंगे कि जिस देश का शासन अपने दैनिक जीवन की आवश्यकतायें जैसे बिजली और पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकता वह अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के समय क्या कर सकेगा? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है।

मैं यहां दिल्ली के सम्बन्ध में ही निवेदन करना चाहता हूं जिस के लिये माननीय अध्यक्ष ने मुझे कहा है। दिल्ली के सम्बन्ध में एक सबकमेटी बनाई गई जोकि इस बात पर चर्चा करेगी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली मे जो बिजली की कमी है उस का क्या कारण है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि केवल कांग्रेस वालों ने ही इस देश का ठेका नहीं लिया बल्कि अन्य लोग भी जोकि देश में रहते हैं वह भी इस देश के हित के लिये चिंतित हैं और उस में अपना योग देना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस कमेटी में सरकारी अफसरों के अलावा जो गैर-सरकारी व्यक्ति लिये गये हैं उन में एक भी नौन कांग्रेसी शामिल नहीं किया गया है। मैं यह गुजारिश नहीं करूंगा कि उस में बिशनचन्द्र सेठ को रक्खा जाये लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आप उस कमेटी में अपोजीशन के आदमियों को भी रक्खें, उन का सहयोग भी आमंत्रित करें ताकि ईमानदारी के साथ यह बात साफ हो सके कि दरअसल किस का कसूर है। अभी तो उस में एक ही कुन्बे के लोग जमा हैं दरअसल सच बात क्या है यह तो भगवान ही जाने सत्य बात हमारे सामने आयेगी भी या नहीं? मैं आप की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्व-पूर्ण विषय है। इसे केवल बिजली और पानी तक ही सीमित मत रखिये। हमारे सामने देश की रक्षा का प्रश्न है। अगर हम ने अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी इस प्रकार असमर्थता प्रकट की तो इस का क्या नतीजा निकलेगा यह आप को बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि उस का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। जो परिस्थितियां चल रही हैं और जिस प्रकार का देश में वातावरण चल रहा है उस के लिये एक बड़े संगठन की देश को आवश्यकता है। उस संगठन के श्रीगणेश ए० बी० सी० डी० में जब बिजली गायब हो जाये तो और संगठन हम क्या करेंगे?

मैं आप के सामने एक और निवेदन करना चाहता भी आवश्यक समझता हूं। मैं अन्य किसी देश के सम्बन्ध में नहीं जानता, लेकिन हमारे देश में एक दुर्भाग्य है। पड़ौसी राज्यों की ओर से हमारे सामने जो खतरे हैं, उनके साथ ही साथ करोड़ों पंचमांगी हमारे में बैठे हैं। अगर आज हमारे देश में कोई इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ कि हम को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ा, तो नतीजा यह होगा कि हमारे देश के रहने वाले कुछ लोग पानी, बिजली, रेल और नहरों आदि को खत्म कर देंगे। प्रश्न यह है कि उस अवस्था में हम किस तरह संसार की छोटी या बड़ी लड़ाई का सामना कर सकेंगे। इस लिये यह नितांत आवश्यक है कि हमारे देश के कम्यूनिकेशन्स, सुरक्षा और दैनिक जीवन सम्बन्धी साधनों के बारे

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

में केन्द्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को बड़ी सावधानी के साथ अपना कार्यक्रम बनाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को बीस मिनट के बजाये पन्द्रह मिनट में ही समाप्त कर अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस से मुझे हौसला हो गया है कि हर एक मेम्बर दस मिनट में खत्म कर सकता है । माननीय सदस्य, श्री बागड़ी, चाहते हैं कि चूंकि उन्होंने जल्दी जाना है, इस लिये उन को पहले मौका दिया जाय । श्री बागड़ी ।

श्री बागड़ी (हिसार) : स्पीकर साहब, आज बिजली के संकट पर, जो कि बिजली बन कर आज भारत के दिल दिल्ली पर पड़ा है, सदन में जो चर्चा का मौका मिला है, उस में हम ने बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना है कि आया यह संकट प्राकृतिक संकट है, ईश्वरीय देन है या यह संकट किसी की गलती या हिमाकत या भोलेपन से हुआ है या यह संकट बेईमानी से और शक्ति के दुरुपयोग से हुआ है ।

अगर यह संकट ईश्वरीय देन है, तब तो उस के ऊपर किसी का क्या चारा चलता है सिवा इस के कि इस सदन के जरिये भारत-वासियों और दिल्ली-वासियों के दिल को मजबूत किया जाये । अगर यह संकट ईश्वरीय देन नहीं है, बल्कि हमारे कर्मचारियों और हाकिमों की बेवकूफी और ना-अहलियत से हुआ है, तो फिर उस के बारे में ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता है कि ऐसे ना-अहल, बेवकूफ़ और गैर-जिम्मेदार आदमियों को हटा कर आगे के लिये अक्लमंद और अहलियत रखने वाले आदमियों के हाथ में यह काम दिया जाये । अगर यह संकट बेईमानी की बिना पर और देश के साथ गद्दारी के कारण हुआ है, तो ऐसे बेईमान और गद्दारों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिये, ताकि आइन्दा वे देश के काज को नुकसान न पहुंचा सकें ।

पहला प्रश्न यह है कि क्या यह संकट ईश्वरीय देन है । क्या यह संकट आसमानी बादलों के टकराव से दिल्ली पर पड़ा है ? पंजाब के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और दिल्ली कारपोरेशन की इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग के बादलों के टकरा जाने से तो यह संकट नहीं पड़ा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकट ईश्वरीय देन नहीं है । यह संकट या हमारी गलतियों की देन है, या सरकार की बेईमानियों की देन है, या जनता के साथ बेवफाई की देन है ।

अब मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि सारी दिल्ली का बिजली का खर्च ६३ हजार किलोवाट है, जिस में से ४८ हजार किलोवाट बिजली रोहतक रोड के ट्रांसफार्मर से मुयस्सर होती है । उस ट्रांसफार्मर से नांगल की बिजली मिलती है और उस के जल जाने से यह संकट पैदा हुआ है । उस ट्रांसफार्मर के जलने से २३ या २४ हजार किलोवाट बिजली मिलनी बन्द हो गई है, जिस से दिल्ली में यह संकट पैदा हो गया है? सवाल यह है कि यह ट्रांसफार्मर क्यों जल गया , कैसे जल गया और अगर जल गया, तो फौरी तौर पर उस का रद्दो-बदल क्यों नहीं हुआ, उस की जगह पर दूसरा ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगाया गया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर कोई भगवान नहीं है कि उस को तब्दील नहीं किया जा सकता है । खुदा और भगवान तो ऐसा है उस को फौरी तौर पर नहीं बदला जा सकता है, वर्ना हिन्दुस्तान क्या दुनिया की किस्मत को बदलने वाले मिनटों में बदल जाते हैं, किसी देश का प्रेजिडेंट या सरकार मिनटों में बदल जाती है । मैं समझता हूं कि मशीनों के युग एक मशीन को खुदा समझ कर दूसरी मशीन को तैयार न रखना ना-अहलियत है ।

जिस ट्रांसफार्मर की उम्र पैंतीस साल की होगी—हमारे माननीय मिनिस्टर साहब से शायद आधी या एक तिहाई—, वह अगर सात साल में मर सकता है, खत्म हो सकता है और इस बात का विश्वास नहीं कि वह पैंतीस साल तक चलेगा, तो हमारे काबिल अफसर, हमारे ईमानदार हुक्मरान किस दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि बिजली पैदा करने वाला वह ट्रांसफार्मर कितनी देर तक जिन्दा रहेगा और वह किस वक्त मर नहीं जायेगा और इस लिये उस के रद्दोबदल के लिये तरीके क्यों नहीं अख्तियार किये गये ?

सिर्फ गलती ही नहीं, उसके साथ धोखा भी किया गया। उसी ट्रांसफार्मर को रिपेयर के लिये गलत पुर्जों का आर्डर दिया गया। तहकीकात करने पर पता लगा कि वे औजार गलत हैं और आज भारत सरकार, जनतन्त्र की सरकार जनता के पैसों को पानी की तरह बहाने वाले पापी लोगों के खिलाफ कोई कदम न उठा कर खुद उस पाप की भागी बन रही है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है—यह शाराह-ए-आम की बात है, जो कि तमाम प्रेस में आ चुकी है।

इस देश में ज्योतिषी और पंडित मशहूर हुआ करते थे, जो कि ज्योतिष और पंडिताई के नाते विवाह और निकाह के दिन बताया करते थे और मृत्यु का दिन भी बता दिया करते थे। लेकिन हमारी सरकार के पंडित बड़े भारी ज्योतिषी हैं। उन्होंने मौत और जिन्दगी दोनों एक दिन बना दिये। पिछले अक्तूबर की २६ तारीख को ट्रांसफार्मर जला और इस जुलाई की २६ तारीख को उस ट्रांसफार्मर की रिपेयर के लिये पुर्जों का इम्पोर्ट लाइसेंस मिलता है।

जब इस बात का जिक्र कारपोरेशन में आया, तो वहां पर एक मेम्बर ने कहा कि जब एक बड़े भारी मिल का एक ट्रांसफार्मर जल गया, तो दो हफ्ते में उस के इम्पोर्ट लाइसेंस की मन्जूरी आ गई, लेकिन तब मेयर साहब ने बड़े अन्दाज़ से कहा कि आप जानते हैं कि इस देश में प्राईवेट सेक्टर का काम चलने की कितनी जरूरत है। मैं अर्ज करूंगा कि यही सब से बड़ी बेईमानी है। इस बेईमानी को सरकार बेशक दबा दे, लेकिन अगर बिजली के महकमे में कोई कत्ल है, कोई डकैती है, इन्सानियत पर कोई जब्र किया गया है, तो इससे बड़ा कत्ल और जब्र नहीं हो सकता है। अगर बिजली के कत्ल की सजा फांसी हो, तो उन हाकिमों की जगह आज फांसी है। अगर इस जुर्म और डकैती की सजा जेलखाना हो, तो मिनिस्टरों और जिम्मेदार हाकिमों की जगह जेलखाना है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : बहुत शेमफुल है।

श्री बागड़ी : मैं अर्ज करूंगा कि मैं नहीं कहता, बल्कि मेयर कहता है कि दो हफ्ते किस तरह गुजार दिये—बेईमानी के तरीके से गुजार दिये। कितना नुकसान हुआ कौम का ! वक्त के मुताबिक इस देश में महापुरुष आये, ऋषि-मुनि आये, पीर पैगम्बर और वली-अल्लाह आये और हाकिम-वक्त की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले भी आये। ऐसा दौर भी आया कि उन आवाजों को सुन कर भी अनसुना किया गया, जिसका नतीजा देश में बहुत बुरा हुआ। जो शक्ति आज सत्तारूढ़ है, वह बेईमानी को भी ईमानदारी का नाम दे कर छिपा लेगी; गुनाह, पाप और गद्दारी को देश-भक्ति का नाम दे कर छिपा लेगी लेकिन वक्त और इतिहास उन गद्दारों को नहीं बख्शेगे, जिन्होंने आज भारत के दिल इस दिल्ली पर इतना गहरा जख्म किया है, इसका इतना नुकसान किया है। क्या वे यह मजाक समझते हैं ? आठ पांच पैसे की ब्लैक-मार्केटिंग करने के लिये किस को पकड़ते हैं ? माचिस वाले को। एक रुपया रिश्वत लेने के लिये किस को पकड़ते हैं ? पुलिस के सिपाही को। क्यों नहीं पकड़े जाते ये मिनिस्टर लोग, जिनकी हुकूमत में भ्रष्टाचार

[श्री बागड़ी]

चलता है ? पिछले अक्तूबर में ट्रांसफार्मर जला और उसके पुर्जों को इम्पोर्ट करने की मंजूरी मिली इस जुलाई में । वहां का इंजीनियर मित्तल अभी तक इंजीनियर है । वह उसके इंचार्ज हैं । वह कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को कुछ न कहो । दो मूर्तियां बैठ करके, यह पचहत्तर सिंह और पंजाब के चौतीस सिंह जो कि चौतीस वोट से जीते हैं, उन्होंने फोटो खिचवा दिया और कह दिया कि अब तो हंगामी हालात के अन्दर सब कुछ कर देंगे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वह कहां गया थे जब अक्तूबर के अन्दर यह ट्रांसफार्मर जला था-----

अध्यक्ष महोदय : अब तक तो मैंने आपको नहीं टोका, लेकिन अब टोकूंगा जरूर । इस पार्लियामेंट में कम से कम यह जाहिर तो होना चाहिये कि आप दूसरों को यकीन कराने की दलीलों से कोशिश कर रहे हैं । आप अपनी बात को जितनी भी शक्ति के साथ कहें मुझे कोई एतराज नहीं है । शायद मैं भी कई बातों में आप से इत्तिफाक करता हूं । मगर आप उस आदमी के बारे में कोई बात न कहें जिसको जवाब देने का मौका न मिल सकता हो । आप किसी का नाम लेकर कोई बात न कहें, यह यहां का रूल है, पार्लियामेंट का रूल है ।

श्री बागड़ी : जो इसके अंदर कंसर्ड हैं, जो इसके लिये जिम्मेवार हैं -----

अध्यक्ष महोदय : आप महकमे को कहते चले जायें और जो चाहें आप कहते चले जायें, लेकिन कोई नाम न लें ।

श्री बागड़ी : चौतीस नम्बरिया मैं नहीं कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : चौंतीस नम्बर और तेंतीस नम्बर का यह सवाल नहीं है । नाम आप नहीं ले सकते हैं उसका जिसको अवसर नहीं मिलेगा कि वह अपनी डिफेंस दे सके ।

श्री बागड़ी : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट तो कहती है कि यह इन्क्वारी बोर्ड आप नहीं बना सकते हैं । यह सरदार प्रताप सिंह कैरो का स्टेटमेंट है । वह कहते हैं कि यह पंजाब से ताल्लुक चीज रखती है । और दिल्ली में बाबा बचित्तर सिंह अपना बोर्ड बनाने को तैयार हैं । जब इन्क्वायरी की बात होती है तब तो उसके वे रजामन्द हो जायेंगे लेकिन जब फांसी की बात होगी तो दोनों में से कोई भी तैयार नहीं -----

अध्यक्ष महोदय : जिनको फांसी मिलेगी वे देखेंगे । मगर आप महकमा बिजली को, कारपोरेशन को कोसते चले जायें, पंजाब गवर्नमेंट को कोसते चले जायें, मिनिस्ट्री को कोसते चले जायें, मुझे कोई एतराज नहीं है । आप कारपोरेशन की जो कमेटी है, उसको कोसें, मुझे कोई एतराज नहीं है । मगर नाम ले कर आपको किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये ।

श्री त्यागी (देहरादून) : कोसने की इजाजत तो मिल गई है ।

श्री बागड़ी : अगर आप लोग खुश हैं इस बात में कि इसी तरीके से देश की दौलत लुटती जाए और आप गीत गाते चले जायें, तो आप लोग जल्दी ही देश को ले डूबेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई ऐसा रिफ्लैक्शन नहीं करना चाहिये कि दूसरे इस बात के लिये खुश हैं । दूसरे मम्बर्ज पर आपको किसी तरह का रिफ्लैक्शन नहीं करना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि वे खुश हैं ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर बात है । कितना ही देश का नुकसान हुआ है । यह मामूली बात नहीं है । अगर देश के साथ इस तरह की गद्दारी और बेईमानी की जा सकती है तो फिर देश के अन्दर और कौन सा बरा काम है

जो किया नहीं जा सकता है । तब तो कोई भी काम किया जा सकता है ।

इसलिए, स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाया जाए । मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारा किसी के प्रति द्वेष है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि किसी को सजा हो ही जाए लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि देश का अगर भविष्य आपको बनाना है तो जो गुनाहगार हैं उनको उन गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिये । इसीलिये मैंने इसको तीन हिस्सों में बांटा है । पहली बात तो यह है कि अगर यह चीज एक्सीडेंटल है, खुदाई की देन है, तब तो किसी का इस पर वश नहीं हो सकता है । अगर यह किसी की नाअहलियत की वजह से हुआ है तो इसको आप बदलो और अगर बेईमानी की वजह से हुआ है तो बेईमानों को आप सजा दो ।

स्पीकर साहब, इससे देश का कितना नुकसान हुआ है इसका अन्दाजा भी आप लगा सकते हैं । कितनी ही एयर-कंडीशनिंग मशीनें, इसकी वजह से खराब हो गई हैं, कितने ही रेफ्रिजेटर खराब हो गये हैं, छोटी मोटी मशीनें बारबार बीच में बिजली के जाने से खराब हो गई हैं, कल कारखानों को इसकी वजह से हजारों लाखों की हानि उठानी पड़ी है, कितने ही मजदूर इसकी वजह से बेकार हो गये हैं और आम जनता को कितने ही दुःख और तकलीफ का सामना करना पड़ा है । यह सब कुछ हुआ है और अब इस सब का क्या नतीजा हुआ है, इसका अन्दाजा हर कोई बड़ी आसानी से लगा सकता है। हां यह बात दूसरी है कि परसों से पहले हम साउथ एवेन्यू में इस बिजली रूप की संकट की वैतरणी नदी से गाय की पूंछ पकड़ कर तैरते रहे हैं और हमारी बिजली तो कटी नहीं और हमारे कनेक्शन में कोई फर्क नहीं आया था । शायद यह इसलिये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोठी साथ लगती है और उनके तथा मिनिस्टर्ज़ के साथ साथ हम भी बच गए .....

अध्यक्ष महोदय : शायद वहां बिजली इसलिये नहीं गई कि बागड़ी जी रहते हैं । यहां तो कटती रही है, बागड़ी जी की नहीं कटी ।

श्री बागड़ी : ऐसी बात नहीं है ।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैंने तकलीफ का अन्दाजा सिर्फ अखबारों को देख कर ही लगाया था । कितना ही सिनेमाज़ को नुकसान हुआ, इंडस्ट्रीज़ को नुक्सान हुआ, मशीनरी को नुक्सान पहुंचा। मैं अन्त में एक सजेशन मिनिस्टर साहब की सेवा में रखना चाहता हूं । यह जो इनक्वायरी होनी है यह किसी मुख्य मंत्री के बोर्ड द्वारा नहीं होनी चाहिये, इलैक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है,उसके ज़रिये नहीं होनी चाहिये, इसको आपको खुद करवाना चाहिये और यह ज्युडीशल इनक्वायरी होनी चाहिये ।जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है, देश के साथ अन्याय किया है, देश को नुक्सान पहुंचाया है देश के धन के साथ बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया है, उनको ज्युडीशल इनक्वायरी करवा कर मुजरिम गरदाना जाए, जेल में डाला जाए । उन लोगों ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी कार्य किया है और बहुत ज्यादा जनता को मुसीबत में डाला है । मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर देश पर बिजली का संकट आए तो जिस तरह से चपड़ासी के घर पर वह आए उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर के घर पर भी आना चाहिये, मिनिस्टर्ज़ के घरों पर भी आना चाहिये । अगर वहां पर एयर-कंडीशनज़ चलते रहे तो पंडित जी को पता नहीं चलेगा कि यह बिजली फेल हो गई है । उस वक्त तक उनको पता नहीं चल सकता है जब तक उनका अपना स्विच बन्द नहीं होगा । उनका स्विच तब बन्द हुआ होगा जब सारे देश में हंगामा मच गया था ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने देश की सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाया है, जिन्होंने बेईमानी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ ज्यूडीशल

[श्री बागड़ी]

इनक्वायरी करवा कर सख्त कार्यवाई की जानी चाहिये, उनको सख्त सज़ा दी जानी चाहिये ताकि इस तरह के तत्व कौमी मफाद को आइंदा नुक्सान न पहुंचा सकें ।

Dr. K. L. Rao (Vijayawada): Mr. Speaker, Sir, shortages of any kind are always irksome. If they are planned, or if they are known before, it is easy to tide over them. But when it comes all of a sudden, as it happened in the case of the Delhi electric supply, it causes a considerable amount of inconvenience and human unhappiness. But it serves the purpose of depicting the deficiencies and the defects of a system. The present failure affords us an opportunity to look into the problem of electrification of the Delhi State.

Delhi derives its power from two sources. Approximately half the power comes from the thermal power station at Delhi and half the power comes from the distant Bhakra Dam project which is about 200 miles away. The load demand of Delhi is also of a different pattern from what generally obtains, for example in the city of Madras. Madras is about the size of Delhi but it has got about two-thirds of the power demand in Delhi.

There are two conspicuous features of the load pattern in Delhi which should be recognised. The first is that it has got an appreciable amount of air-conditioning incorporated in it. Secondly, in this great city, the Capital of our country, we are playing host to a large number of foreigners. Therefore we should assure them on all occasions unrestricted or unfailing source of electrical energy. These two requirements we must keep in view when we are discussing the question of the shortage of power.

It is a very interesting statistical coincidence that we are putting into pipes from the Wazirabad Barrage on the Yamuna the same amount of water in millions of gallons per day—it is about 94—as we are putting power into the wires of our power system; that also is about the same, that is, 94 megawatts. In respect of both water and power we have got shortages. In respect of these two, we have got to have a certain fundamental policy, or we must have a certain fundamental concept. Take, for example, the water supply of Delhi. Delhi is an ancient city which has been built on the banks of a very great river, Yamuna, a river which has a perenial water supply. Its minimum discharge on any day is 4,000 cusecs. Normally, therefore, there must be plenty of water even in the leanest day in the Yamuna for satisfying the needs of Delhi which, on a future day, will consume only about 400 cusecs. What happened was, some years back, Punjab and the U.P. have constructed a barrage across this river about 150 miles away from Delhi at Tajewala and diverted all the water, with the result that Delhi, the drinking water for which is the first charge on the river has been forgotten and we are now finding it very difficult to find a substitute for this water. The water requirements to make up the shortage for three months is very small, what we call 3000 million cubic feet. Even this small quantity we are finding it difficult to make up because this fundamental concept has not been accepted, namely, that Delhi city must form the first charge on the States of Punjab and U.P. which are the contiguous' States for supplying water and power. Apart from the fact that Delhi's drinking water must have been the first charge on the Yamuna river, the natural resources that must be developed for the benefit of Delhi are located in these two States. Therefore, we should take a definite policy decision—I am not talking financially; finances, of course, the Centre has got to bear—that from the point of view of supply of water and power to Delhi city, it must be the prime responsibility of the States of Punjab and U.P. which are the contiguous ones to this great city of Delhi. It has not been accepted or at least

well understood. In its absence endless meetings are taking place at which no decisions are taken and the problems confronting Delhi remain unsolved.

Delhi city presents, in respect of electricity, a picture of un-coordinated planning. For example, there is Bhakra power supply to us; there is thermal power supply to us. But, they are not connected together. That is to say, areas which are served in the Delhi city by the thermal station, except for a small portion, cannot be served by Bhakra power. Really what they do in all great cities is to provide a ring feeder to which all the lines from different sources of supply are connected so that it would be possible to change over in a case of emergency from one to the other. That has not been done at Delhi. Also there must be stand-by capacity in the line. That is to say, when we get power from Bhakra, it should not be for half the load in Delhi city, but the line must be capable of having full load capacity. It is only then that in cases of emergency, we can switch on to the Bhakra line or either way. Therefore, there should be full capacity, emergency capacity in the line.

Thirdly, we should have connected the U.P. grid. We have in the Ganga and the Sarada quite a large amount of secondary power; especially in the monsoon months, we have plenty of water in the Ganga and Sarada rivers. We have got only to turn the wheels with water to produce the power for a few months, at least for the monsoon months, for nearly 6 months in a year. That power could have been fed into the lines which are only twenty miles from Delhi. If the connections to Delhi had been constructed, we should have overcome the deficiency from which we are at present suffering. These are instances I have just mentioned to show how there is not a co-ordinated planning in the system of Delhi electric supply system.

Coming down to the very immediate problem, the unfortunate occurrence that have taken place in Rohtak, it is very mysterious that two transformers which must have served very robustly for a number of years, must have failed in succession, in the course of one year. A Transformer is an equipment where there is no motion, there is no rotation, no movement of any kind whatsoever. It only consists of three limbs on which the coils are wound three different coils, insulated one from the other. It is a very robust equipment and it should not fail. It is surprising that one machine failed ten months back and another machine failed now. The reasons for this, of course, the committee that has been appointed will go into thoroughly and try to find out why or how this happened, who has tested this, or why the testing has not been done, who is responsible for the purchase and how this kind of defective material has been put in this very vital link between Bhakra and Delhi.

It is not so much with the above that I am concerned now. When the first transformer failed 10 months back, what were we doing all these months? Why was it not put right? We have not taken any energetic steps for that. That is a serious matter. That is one thing I am not able to understand. Similarly, a proposal was approved to put in another 30,000 kw. by way of extension to the existing thermal power station. To place an order for this, we have taken 1½ to 2 years.

These are some of the instances which indicate that we should have an organisation which is different from what we are having in the Delhi Electric Supply Undertaking. The Delhi Electric Supply Undertaking is more or less a department of the Corporation. That won't do. What we should have is a better organisation, something like a State Electricity Board, with a technical man at the head. I am emphatic about it that there should be an Electrical engineer in charge of the undertaking. If the whole generation and distribution of power in Delhi is put in charge of such a State authority, working not

[Dr. K. L. Rao]

under the Corporation, but directly under the Ministry of Irrigation and Power,—I am sure such kind of shortages and difficulties will not occur in this great capital city.

There is another reason why we should take this step immediately. That reason is vital. At present, the amount of power that we are utilising is about 94,000 kw. both from thermal and Bhakra. I am certain that in another 10 years, this load is going to be 500,000 or half a million kw. That is a big power. It cannot be managed by an organisation of the present type. It is very necessary that we should have an organisation which I have indicated earlier.

There is also another important matter which we should remember in this connection. We should not commit the blunder of raising this power supply by means of thermal power stations. Delhi is located nearly 1000 miles away from the coal fields. To transport all the coal here is not economical. More than that, we have got the mighty Himalayas, the treasure house of electric power right within a distance of 200 miles. You have got a number of beautiful schemes in the Himalayas: for example, on the tributaries of the Yamuna or the Tons, or on the tributaries of the Ganga, like the Topovan project on the Dowlingana or on the Bhagirathi. There are so many tributaries of the Ganga on which we can develop projects, by the mere run of the streams. All that need to be done is, merely to put in a small barrage and take the water down. There is a fall of 2000 feet, or even more than what we get in the Western Ghats. Out of the fall of 2000 feet, we can generate enough power, sufficient for the Delhi city. Therefore, Delhi city must be linked up with a perpetual source of power, hydro power and not with thermal stations. Of course, I can cite a number of cities where similar developments have taken place. For example, there is the city of Seattle in the north-west corner of the U.S.A. That city is located similarly within 200 miles from the mountains. What they have done is this. There is plenty of coal and oil also within easy reach. They have not resorted to these fuels. They have constructed the Ross dam under very difficult conditions and all the generated power is supplied to the city of Seattle. The Delhi power supply must come from hydro power stations and not from thermal stations.

We must take this opportunity to scrap the thermal station that we have in Delhi. We have got in Delhi a thermal station which is highly inefficient. That is to say, we have got units of 12 megawatts. At the present day, science has advanced to this extent that we have got units of 100 megawatts and 700 megawatts each. To have a small unit of 12 megawatts and to run it at low pressure is very bad and uneconomic. Because, we are consuming coal at the rate of twice which we should have consumed for the same amount of power. In other words, a train load we are taking a day, of 1000 tons, whereas it should have been 1000 tons every alternate day. So, that, when we are planning on comprehensive scale we should so plan that we scrap the present plant. There are so many places in India which require thermal power. We can place it near the coal fields. We should take an early opportunity for that. Of course, the thermal station can be a stand-by. But, let it be a more efficient plant because we are far away from the coal fields. Therefore, in this picture of planning, we have got a big duty to do to Delhi. That is to say, we have got to plan out for the future; it is not a distant future, but it is a near future for which we have to plan; in another ten years, we shall be faced with half a million kw. of power requirement. There are many buildings today where no air-conditioning has been installed, because we do not have enough power. So many tall and high buildings have been constructed with a lot of provision of air-condi-

tioning facilities, but none of them is being provided, because we are famine stricken in regard to power, though we have got ample opportunity for developing power.

Therefore, I submit that this shortage that has occurred now should be taken as a lesson. It is a thing where we should try and now itself plan out a good organisation and see that we get the benefit thereof.

Then, I come to the question of tiding over the present difficulty. There are only two or three methods for it. One is this, and, of course, they are already taking that up; there is a 220 k.v line coming from Bhakra; that should be expedited as early as possible. There is also necessity for us to search all round India and find out if there is any transformer available. We must be ready with those things. What we are now trying to do is to take one limb from one sick equipment and put it on another. And by the 25th of August, it may just happen again that still that does not work, and so, this kind of shedding must go on for ever. Therefore, we should anticipate things and be prepared with these things, and we should be ready by getting some transformer from some other place. We should also expedite the 200,00 k.w. line from Bhakra, as I pointed out earlier.

There is one other important factor that we should remember and that is a very vital need of the hour, and that is that we should take steps to produce our own equipment in this country. It is one of the very saddest things that we are not able to produce a transformer in this country. The transformer is a very simple equipment and we are unable to manufacture that in this country. We have got to purchase from other countries. What is the use of the Bhopal factory and other factories on which we are spending so much of money? We should expedite and put in work round the clock for all the twenty-four hours of the day and manufacture this equipment; and we must quicken the pace of production of this equipment in this country. That is a very vital need of the country today. We have put power as the first item on the agenda for national development, and we should take immediate steps to ensure smooth fulfilment of this purpose. I should only say that the lesson of Delhi should be the lesson for India.

Shri Frank Anthony (Nominated—Anglo-Indians): I find it difficult to speak with my usual restraint in this discussion. My hon. friend who has spoken before me has spoken obviously with specialised knowledge. He has tried to rationalise what has been euphemistically described as a power crisis. But in the final analysis, this is not only a power crisis; in my respectful view, it is a crisis of the administration, and I do not think that I am exaggerating when I say that since the killings, there has been no more shameful breakdown of the administration in Delhi.

My hon friend who just spoke perhaps, in spite of himself, underlined inefficiency. In spite of himself, he underlined the obvious negligence. And it would appear to be not only a long but a sordid story, a man-made crisis and after the crisis supervened extraordinary callousness, almost criminal indifference to what the people in Delhi have had to put up with. It would appear that those in the seats of power have not been affected, or if they have been affected, they have been affected very little. I do not know whether these cuts, and this shedding of power has affected their rarefied living. I am just wondering whether those in the seats of power have any conception of what it has cost the people of Delhi, whether they realise that trade, industry and business have been largely crippled, that tens of thousands of daily paidworkers have been thrown out of work, not to speak of the little children who have had to swelter because they have never known from day to day what your so-called schedule has been; I wonder

[Shri Frank Anthony]

whether they realise the millions of difficulties and sufferings which have not found expression or publicity.

What really disturbs me is that this is a sort of omen of what is happening in the administration throughout the country. It is a disturbing omen, not only of negligence, not only of incorrigible ineptitude, but above all, of sheer nervelessness in the administration. I do not want to go away from the subject, but it is symptomatic of what is taking place largely in the administration throughout the country. Ineptitude precipitates a crisis; when the crisis supervenes, the civilian officials are not able to face up to it. This is what is happening in other parts of the country too. I am only illustrating it. There is negligence leading to civil commotion, civil commotion in which the police, if they do not join in the looting and murder of minorities stand by; and in the final analysis, the military have to be called in, because the military today represents the only segment of the administration in which the people still continue to have any confidence. I am only sorry that when there was this shameful breakdown of the administration, we did not call in the military. I am quite certain that instead of all the excuses and all the alibis that are bond to be trotted out, if this has been handed over to the military, within a week we would not have continued to suffer from ordeal that we are still undergoing.

The facts have already been detailed As I said, the sordid story stands out blatantly. There were two transformers; obviously, one must be a standby to another One failed in October I do not know, but one of the reasons in the press was that suddenly the Government, which if it has made any progress, has made a rake's progress, which has never bothered about spending and wasting crores, not to speak of lakhs, suddenly became overcome by qualms of conscience about spending Rs 1.80 lakhs on this stand-by transformer. I fail really to understand this position. Here was a stand-by transformer representing literally the power-life-line to the capital, and they dawdled about spending Rs. 1.80 lakhs on this stand-by transformer. Then, what happened? And they dragged their feet typically. One of the less moronic officials—apparently the whole hierarchy was moronic-took about a week to discover that there was a transformer available in Nangal. I want to ask the question. When you had this breakdown of the administration—it was not a power crisis—could you not have found out whether any other transformer was available anywhere else in the country? Could you not have imported one? Somebody said that it was so heavy that you would have had to have a special ship. I do not quite know. I was talking to some Air Force chaps, and they said that some of their 'planes could carry not one but five transformers . Surely, it was a crisis which was serious enough, oppressive enough, to warrant our going to beg, borrow or steal a transformer and from somewhere in the first three or four days, the schedule was advertised, and to some extent, the administration adhered to it. But since then, in fact, today, in my own place, I have had an unscheduled cut for five hours.

Shri Nath Pai (Rajapur): We have also had it.

Shri Frank Anthony: I do not know; I am not quarrelling with the Prime Minister. He has a heavy schedule. But many of us have as heavy and probably a more brutally heavy schedule, and unlike some of the Members on the Treasury Benches, we have to earn an honest living, and earning an honest living means working to a brutally heavy schedule. Whether all the Ministers or Deputy Ministers do not work may not matter; some people say that if they do not work, the administration may improve; some others say that if they are taken off the working

list, the most it can do is to add a little to the unemployment problem but not very much.

What has happened since this breakdown? It is utter and complete chaos. One day, I phoned the New Delhi Municipality, and the man said 'Your office will have power cut from 1 to 4 p.m.! So, I told my staff to come in at 8 a.m. They came and they had barely settled down to work, and the cut was from 8 to 11 a.m. In my public school, where I cater to a thousand little children, they told us that the cut would be from 1 p.m. to 4 p.m. and we asked the children to come to school from 9 am. to 1 p.m. One that particular day, they came at 9 a.m., and the cut was from 9a.m. to 1 p.m.! It is utter and complete and absolute chaos. When the Chinese have not moved one 'plane, one gun, one Chinaman against us, Delhi today is in the condition of a conquered city completely chaotic, with a complete breakdown of the administration. I say it is a classic example of an increasingly ramshackle demoralised administration collapsing under the weight of its own inertia and sheer ineptitude. At one time, when I was younger, very few people could equal me in my capacity for vitriol. But today I am bereft of adequate words to describe what has happened to the people of Delhi.

Mr. Speaker: He is mistaken there. He still maintains the same vigour and vitality.

Shri Frank Anthony: It is a national characteristic. We are nothing if we are not mealy-mouthed hypocrites. It is almost a national characteristic. So we have made an offering to this nations characteristic. We have set up an Inquiry Committee. And look at the history of this Inquiry Committee. The Inquiry Committee was set up. One of the members—I will not name him— was a person who was in the middle of this very crisis. If any culpability is going to be fixed, it will be fixed squarely on him.

Then, of course, we get this rather unseemly sorry spectacle of a conflict between the Centre and the State Government as to which subject this is. Is this a State subject or is this a Union subject? I will not argue that because as a lawyer I could say that this is very much a Union subject, and you should have told the Punjab Government. It is presumptuous on your part to tell us that it is not a State subject because electricity is in the Concurrent List' and Delhi is a Union territory. If a grave emergency like this occurs, it is the ineluctable duty of the Centre to assume the responsibilty. If incidentally you do say somethink about the Rohtak power, it is only incidental. Then even if you have two distinct entries .if you have the power to legislate with regard to one. then, according to the doctrine of pith of substance, even if you incidentally trench on the other, it is not improper. Here incidentally you may even find the Chief Engineer guilty. It does not matter. I was surprised at the susceptibilities of people.

I do not know what is going to happen with this Inquiry Committee. But I have grave doubts whether anything will come out of it except a great deal of white-washing for the Government But I want to ask this question. When you have an ordinary railway accident, when one person is killed, all the people directly responsible are suspended Why did you not suspend all the people who were directly responsible? Not the Chief Minister. Suspension does not mean prejudging of their guilt. It is done with regard to every railway accident. If the inquiry exonerates them, they are reinstatd. As I say this is a reffection of the complete inertia and criminal complacency of the Government. Not one person has been suspended. And I have grave doubts about this. After all, the engineers are a privileged fraternity. If they have not got friends among the Ministers, they have friends

[Shri Frank Anthony]

at least among Deputy Ministers. So nothing is going to happen.

The point that grieves me is this. It is not only a reflection on the administration, our capacity to administer the country in peacetime, but I am really grieved by this and feel hurt and resentful. When I drink with some foreigners—I have some foreign friends here—I find we have become the laughing stock of the foreigners in this country.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): After the forceful speech of my hon. friend, Shri Frank Anthony, I would like to add my voice to condemn the administrative breakdown. There is one good thing about this debate, because it is now focussing attention on the power crisis, a man-made crisis, right throughout the country. It is only because Ministers and Members of Parliament are suffering today in the city of Delhi that they will now be prepared to understand to what extent big cities like Calcutta and the entire industrial belt in West Bengal and Bihar have been suffering for the last one year. We tried to raise this matter in the House last year but got a most unsatisfactory reply from the Minister. Unfortunately, I must say, this House did not take this matter seriously at all. We had expected all sections of the House to rise to the occasion and have the matter pinned down, because what has happened in Delhi today is what has been happening for one whole year now in the States of West Bengal and Bihar.

One of the most important things in these matters is planning. Planning without power—what is that planning worth? What has happened to the Bihar—Bengal coal belt? Today they say that the whole thing is going to stop unless absolute, top number one priority is given for the supply of power to the West Bengal-Bihar coal belt. Are you able to do it? What has happened. there? It is the same thing that has happened here in Delhi. There has been a conflict as to the entire question of this DVC, whether it is capable of supplying power as well as looking after flood control measures and irrigation supply channels. It has also been a problem as to how much of it has to be supplied through private companies like the Calcutta Electric Supply Corporation. The same thing, breakdown of generators, happened there last year. All the transformers of the Calcutta Electric Supply Corporation, which was getting cheap DVC power and selling it to the people at a much higher rate, broke down together with the transformers both at Bokaro and Durgapur. In this very House, we raised this question as to why it happened. One of the reasons which was adduced by certain technical people was that the generators were bought from West Germany and they were not supposed to be good, they were not the ones that were technically efficient. Who bought them? Why were they bought? Nothing has been done to pin down responsibility.

Today when we come to consider the Delhi power crisis, we find the same thing. We are told that the life of a transformer is 35 years. Our hon. friend, Dr. K. L. Rao, has told us that these are sturdy machines. Then how is it that they go out of order in seven years? Who is responsible for it? Why has it happened?

This is really a very sorry state of affairs. The administration goes and buys these things from abroad. It is not a question of import only. Once you import them, you find that they are not functioning properly. Who ordered it? Is it the best? Has it been put to use in the proper manner? Nobody cares. We say, 'bring in spares.' Certainly, we should have spares. But why is it that the original ones both at Bokaro and Durgapur as well as in Delhi did not function properly? I am told that the Delhi ones are British. How is it that they did not work well? Have we tackled that? Have

we found out whether they have been used in the right way? All these things, I find, are being duplicated from end to end.

Not only that. Look at the dilatory tactics. What has happened in the case of West Bengal has again happened in the case of Delhi. The Delhi transformer went out of action in October. We are told that import licence was got in July. In West Bengal, when the Third Plan was being formulated, as regards power, we were reaching a stage of acute crisis. After six months the Sachdev Committee Report comes. Now after another six months nothing is done. Here is an article written in the *Statesman* at that time. Now a year has passed and still we do not know what has been done to supply the extremely urgent needs of this section of India which is going to supply coal, steel and alloy tool steel to all the big industries

Here also we are worried about the foreigners, and about air-conditioners working in the capital. I am not so much worried about that. Let the foreigners see what we are. I am not worried about that. What I am worried about is the running of our industries, our own work. The Prime Minister always tells us that workers do not work. You do not give proper basic wages to the workers. The wages are kept so low. Yet they are told to increase production and get incentive bonus. Everyday for the last so many months, all our mills have been staggered. They have to work round the clock. Workers have to work every day in the week. There is not one day in the week when they can have a holiday. In spite of this, the basic wages are low. They do not get production bonus; they do not get incentive bonus. This is the situation to which we have reduced ourselves. Not only that. See how beautiful the planning has been. May be it is the same here, but I know a little more about West Bengal. They say after the breakdown in West Bengal that the turbines had reached before the boilers, when actually the boilers had to reach first, and they were kept waiting till the boilers came. Is this planning? The Sachdev Committee Report has pointed out that this is the state of affairs.

16 hrs.

Shri Tyagi: Where did it happen?

Shrimati Renu Chakravartty: In Chandrapura in West Bengal. This is what the report says:

> "Meanwhile, work in connection with the West Bengal Government's thermal station at Bandel got off to a good start recently, and the DVC's power station at Chandrapura (with two generators of 125 mW each to start with) is making rapid progress. At Chandrapura, for which the DVC will receive a DLF loan, work on the boilers is almost complete. Curiously, turbines, which have to be installed after the boilers, have reached the plant site before the boilers."

So, this is what has happened. When there is a breakdown of a transformer, it takes us eight months to get another. When we need the boiler, we get the turbine, when we need the turbine we get the boiler. If this is not inefficiency or madness or, shall we say, sabotage, what is it?

What Shri Anthony says is quite right. What is the use of these enquiry committees where you put in those very people who are actually responsible for this state of affairs?

In West Bengal, what has happened? A situation has been created in which every day we have to go to the U.P. Government and beg them for more power from Rihand, to Bihar for increasing DVC power allocation. Bihar has to come to Bengal. There is no over-all policy regarding priority, as to the sector which will be fed first, nothing has been done.

In this situation, the Jaldhaka hydel project in North Bengal has also not been sanctioned. I entirely agree

[Shrimati Renu Chakravartty]

with Dr. Rao, though I am not a technical person, but having been associated with the family which 30 years ago brought into being the hydro-electrict project to feed Shillong, I know something about it, and my father used to say that hydro-electric power is the cheapest form of power, and we have plenty of that, but this project has been cut out by the Planning Commission.

So, what is the planning, what are we doing? Now we are told that Rihand would give us enough, and so the Jaldhaka project has been given up, we cannot get that hydro-electric project.

May I inform the hon. Minister and the other Members of the House that in the big city of Calcutta, with a population of 7 million, every day we have power cuts, but it has not come to the forefront because people are not interested except when something happens in Delhi. This is the position. So, I beg of this House as well as the Government to note that this is a point on which we indict the Ministry, the Planning Commission and not only the administration. I am not going to allow the Planning Commission and the Ministry to get away with it. For a year we have been asking the Ministry for a satisfactory reply, but we have got none. Let them tell us whether they have been able to settle their differences with the State, work out a general policy; let them tell us that this is the prority that they have set out and this is the plan they are going to execute.

Power is the first essential of planning, and unless we can give that power, we have no right whatsoever to talk in the name of planning or to advise the workers to produce more saying that everything depends upon production. We cannot say that planning depends upon exports and exports on more production

So, this entire matter has to be gone into. It is not just a question of getting a turbine from here or there. That is a comparatively small matter, but this entire matter must be taken up with the greatest seriousness by all the Members and Parliament and we must see to it that those responsible for this failure, dilatoriness and sabotage are brought to book.

Shri Nambiar (Tiruchirapali): He is a powerful person speaking on power.

Shri Tyagi: He is going to shed power.

Shri Hanumanthaiya (Bangalore city): I am much beholden to the hon. Members who pay me some compliments.

Some Members who spoke in Hindi accused us of always praising the Ministers and making them work in the fashion they have done, but I can assure them that that accusation is wholly inapplicable in this case. So far as the failure of power and its consequences are concerned, all those who are in this House are of one mind If I understand it correctly, even the hon. Ministers who, for the time being, have the opportunity of administering the Ministry, are also not happy. It may be that inefficiency, as Shri Anthony vehemently described, has dogged our footsteps; it may be, Dr. Rao described, improper planning and want of vision has landed us in the situation in which we find ourselves today.

Many a time I have noticed on the Treasury Benches want of co-ordination between one Ministry and another. On such a discussion as this, a very important discussion, particularly the Minister in charge of Planning should have been present. A discussion may pertain to one Ministry technically, but it has repercusions on other Ministries. But the other Ministers do not take the necessary trouble of turning up and listening to the Members, and of getting into the mood and feelings of the Members. That is the first requirement that ought to be fulfilled by the concerned Ministers. If the Planning Minister

was here, he would certainly note in his mind at least how deficient the planning is.

We come from far off places. Not only in electricity, but in many respects the picture of Delhi for us is a picture of deficiency—in the matter of discipline, in the matter of orderliness, in the matter of efficiency, and I might say, in the matter of honesty also. People come here, wander in the Secretariat, and spend a hundred or two hundred rupees a day in hotels If people can spend money so lavishly in a city, that is proof enough that there is something wrong in such a city and such a situation. It is not any particular individual that is to blame. it is the system. I am speaking not as a technical man, but as a man who is interested in the administration.

One more lacuna in planning has been the fact that they did not envisage the growth of Delhi. They planned the production of electricity, but they allowed Delhi to grow so enormously and so hugely that the problem has become insoluble not only in the matter of electric supply, but also in the matter of housing, water supply and other respects. The people who have been put in charge of planning—no argument whatever is required to prove it—have not been equal to the occasion. They might have been equal to what is called the requirement of favouritism so far as continuance in their respective posts concerned, but they have not proved before the country and before the House that they were up to the mark so far as planning and vision are concerned.

In this note which has been drafted by the Ministry, they have said almost innocently:

"Foreign Embassies and others who have their own generating plants as stand-by have been requested to commission them and reduce the consumption from the general system."

If foreign Embassies have been continuously in doubt about the efficiency of the Delhi administration or any other administration, regarding the continuous and efficient supply of power, it is a permanent disgrace on that administraton. Instead of feeling ashamed of such a situation, to ask them to supply power is like the eternal begging bowl going round the world for aid—financial aid, food aid, grain aid and now electricity aid.

The other day, one of the hon. Ministers, Shri Krishna Menon said that we are a sovereign and self-respecting nation. Maybe, we are sovereign; everybody may accept it. But whether we are a self-respecting nation, I want the hon. Ministers to coolly think over it and see whether we deserve this compliment with this kind of planning, with this inefficiency and irresponsibility.

In the Delhi Administration, whether it is the Central Administration or whether it is the Corporation administration, there is evident deficiency, not only in efficiency as I say but also in responsibility.

I offer a suggestion with all the seriousness that I am capable of. So far as the essential services are concerned, the supply of water and electricity etc., any failure or any mistake must not be looked at in the usual sense of dismissal or disciplinary action. It must be considered as a penal offence. It is only then that our lethargic officers or others concerned will wake up to the situation. Whether it is a railway accident or whether it is the failure of electricity, it must be made an offence under the Penal Code. The situation has deteriorated to such an extent that there is no other lesser remedy.

Shri Rao said that this crisis, what is called the burning of the transformer came suddenly. I have made a little enquiry. It is not true. It was there for a long time, almost a year ago. That is what people told me—and it has to be taken for what it is

[Shri Hanumanthaiya]

worth because I have no personal knowledge. The generator was so over-worked that water was being thrown over it to keep it cool. It went on for a number of days. In spite of that the concerned engineers and the higher authorities did not wake up. The transformer was giving visible proof that it will break down any time. It was by this manual method of throwing water on it that it was being maintained. To say that this power crisis came suddenly and accidentally is not true.

So far as the committee that has been appointed by the Government of India to enquire into it is concerned, I beg of my hon. friends not to be prejudiced without knowing the situation. It may be that each one of us has a good opinion or a bad opinion of individuals. We are not concerned with any group politics or party politics, we think that the particular gentleman referred to by one or two members has had the administrative experience of the place. He knows everything from beginning to end and let us give some credit to him as we give to ourselves. He is also an hon. Member of this House as his critics. He would be dicharging his duties as patriotically and honestly as the two critics who have made allegations against him. Therefore, we must always proceed according to the legal maximum that a man cannot be said to be guilty unless he is proved to be guilty. We cannot be said to be guilty unless he is proved to be guilty. We cannot presume a man to be guilty.

Therefore, this committee which has been appointed will, I hope, be able to give an impartial report. More than that it has to make suggestions. And, I hope one of the suggestions would be to make that in a failure or accident of this kind who ever is responsible is criminally responsible, that is. he must be hauled up before a court of law for the death of persons or for other inconveniences caused.

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): Mr. Speaker, Sir, may I humbly suggest that power brings trouble and corruption? This is electrical power and it has disturbed the civilised people in our capital. We are able today to find the errors of Government. Normally, Government teaches us lessons on what to do and what not to do. But, today, we are in a position to find out the errors of Government. I am glad our urban people have found out how uncomfortable it is without electricity.

We in the South Avenue were not much troubled with this power crisis. But since last two days we have also personally suffered inconvenience. And, day before yesterday, when I went out for a hair-cut, I had to move about in Connaught Circus for two hours because no hair-cutting saloon could take me in. They could not work without light. (*Interruption*). If my hon. friends on the Treasury Benches were to have a vote of confidence from Delhi city, till this power crisis is on, I am sure they will not get in full.

Mr. Speaker: Without that experience, probably, the hon. Member might not have chosen to speak today.

श्री त्यागी : जनाब की तो हजामत हुई नहीं, चल पड़े मिनिस्टर साहब की हजामत करने ।

Shri Narendra Singh Mahida: I have seen government officers and clerks in the North Block recently. (*Interruption*). They had to remove their coats and shirts and keep all the doors and windows open to remain cool. I am sure the government officials will agree with us—privately, of course—(*Interruption*). When reprimand the Government.

Wherever, there is machinery, there is bound to be trouble. But in the case of an important city like ours, which is the capital of the country, incidents are taken notice of by the whole country. This major power

failure is a very shameful affair, not for the Government alone but for us Indians as a whole, that we cannot manage even a small affair like the electric supply to this capital. It is a bad reflection on our State of affairs and I must bring it to the notice of the House that merely expressing our views here is not sufficient. We should very severely reprimand the Government; we should do more than that. to show what poor consideration they have given to this supply of electricity.

Even in my town of Baroda the supply is dual; one from the Surat thermal station and the other from the Ahmedabad thermal station. We always have an alternate power supply. I am really very surprised that our worthy Planning Commission or other government officials have never thought of a dual supply for a large city like the capital of India. There must be and there should be a stand-by supply to the city whereby the conveniences of the people are managed efficiently and well.

I agree with Shri Frank Anthony about the foreigners, whom I have met during the last two days and they have laughed and joked in a very humorous way, of course at this power crisis. One can see their feelings towards these inconveniences. We are a civilised people living in this city and are in full enjoyment of air conditioners and fans and we are disturbed when they do not work. But in the rural parts where there is no electricity I think people are happier because they have not enjoyed these facilities; they are doing without them. That shows the progress of civilisation and how human beings are unable to put up with little difficulties here and there. I am not reflecting. I am just pointing out that the major part of the country is a rural area; it is not affected by the presence or absence of electricity. If the Government comes with all humility and says that this is a *bona fide* mistake of a particular officer or of breakdown of some machines, we shall put up with these things and request the Government to put in order the transformer or whatever parts are damaged. A small transformer can be brought from any other part of the country or even imported under very special circumstances. I know that the committee of enquiry has been appointed and it will submit its report by the end of this month. The officials of the power supply departments have assured that they would be able to work the transformer by the 25th instant: I think it will synchronise with the submission of the report. Till then nothing will be done and I do not know what I should say further in the matter except to complain very bitterly not only as a Member of Parliament but as a civilised Indian that such a state of affairs exists in the capital. We must improve our affairs and put things right.

Shri Shiv Charan Gupta (Delhi Sadar): Mr. Speaker, in the first instance I was rather reluctant to speak on this subject.

Mr. Speaker: Why has he shed that reluctance?

Shri Shiv Charan Gupta: But today there was a further breakdown of electricity in the City and my patience was also exhausted. Shri Frank Anthony said that there were five hours of shedding today. That was not accidental. But there was another breakdown in the power supply.

Shri Frank Anthony: Unscheduled.

Shri Ansar Harvani (Bisauli): Has the Minister any information about it?

Shri Shiv Charan Gupta: I do not know. This is due to lack of sufficient water in river Jumna. I think it is a very serious matter that people here should suffer on account of accidents to the transformers and now on account of insufficient water in river Jumna.

Shrimati Renu Chakravartty: Why? This is a thermal supply.

Shri Shiv Charan Gupta: What is surprising is that every year some difficulty arises from river Jumna during this season because we have to take water for cooling the boilers to and for certain other purposes also. The Delhi Electricity Supply Undertaking say that people at Tejawala headworks do not consider this point and sufficient water is not available. On account of this state of affairs, life in the city is already paralysed. Small businessmen, manufacturers and workers working from morning till evening are faced with a lot of difficulties and now we are faced with another problem. We may say that in the last fifteen years electric generating capacity has been increased from 30,000 to 94,000 kws. In place of 29,000 we have two lakh electric connections in Delhi; that in every Plan due attention had been given to power supply in Delhi and to the country. But all this will be of no use if these are not supported by the administration. There are genuine and honest and sincere officers. But we should not forget that there are so many internal rings and cliques in the administration; they spoil the whole thing. If the Government does not take into account all these factors there will be more trouble. We are suffering from shortage of water supply also. Even if water is available in Jumna and if Punjab releases water, water will not be available on 1st, 2nd and subsequent flows because the distribution mains are not sufficient. When you want pipes for laying these mains, the manufacturers say they have no stocks of the G. I. pipes. Today there is trouble from Punjab; next day there is some internal trouble. We are having accidents in Delhi. During the last four or five months, there has not been one day when there was not a break-down of electricity in the city. Sometimes it is due to old distribution lines; sometimes it is due to excess or unauthorised load drawn by some anti-social elements in the city. Thousands of kws. are used without any authorisation in Delhi. Honest people and law abiding citizens suffer on account of some cliques among some people. Instead of 3 H. P. load sanctioned, they are utilising 30 H. P. load. Things are going on like that.

Then there is the question of maintenance. I will tell you one incident. Last year there were accidents in the city and I found that such and such a man was responsible. That man was pulled up. The next day things were all right. What does it show? It shows that all is not well with our administration. If we are not able to correct it, we will be faced with many difficulties. I agree with Dr. Rao that we should not entirely depend upon the generating capacity of the DESU or the supply from Punjab. Delhi is the capital of the country and electricity is the lifeline of the whole country, much more so, of the capital. Therefore, it should be connected with the adjoining State so that whenever there is any breakdown of power in the capital, the city is not affected and the supply remains normal. So, I would submit that whereas this enquiry committee is going on into the causes of the breakdown, a high-power committee should be appointed by the Government to ensure that electricity in Delhi is always available and by such accidents—may be sometimes these are due to fifth columnists. —the normal life is not disturbed.

Of course, Dr. Rao said something about the transformer and I agree with him. One of the ransformers was burnt out on the 26th July. But you will be surprised that a "Hungarian" transformer came from Nangal, but the officers did not instal that transformer. Well, I do not know whether there is some purpose behind it—but I definitely say that his is a very serious matter.

Shri Nambiar: Red.

Shri Shiv Charan Gupta: If that transformer had been installed by now the electric supply would have been

normal in Delhi. I want to submit one more point. It was reported in the papers that one transformer was burnt in October last and there was a long correspondence with the Government of India. The Government of India did not issue an import permit for the purchase of spare-parts. That is a sad commentary on our work. At the same time, these electrical goods, ranstormers and oher machinery, are imported and there are well-known manufacturers. There is a doubt in the mind of the people that here is a clique in which high officers are involved with these manufacturers with some anti-social motive.

Shrimati Renu Chakravartty: That is absolutely correct.

Shri Shiv Charan Gupta: I do not want to say more on this subject. But I would urge upon the enquiry committee, because it is manned by highly respected people, that they should go thoroughly into this matter and see that all those persons who are at fault are taken to task. I wish to submit that we have to take adequate steps in this direction; more particularly because of our differences with China, more particularly because of our differences with Pakistan , such accidents should not be repeated in the capital. I am not saying this because I represent a part of Delhi, but I say this because I feel that if this is the state of affairs in the capital, the impression that it will create would be bad. What impression will it create in the mind of those people with whom we are not on friendly terms and who are challenging our sovereignty? Therefore, I submit that we should take the necessary steps, and the Government should move immediately in the matter and take proper steps so that there is no repetition of these accidents.

Shri Priya Gupta: I am very happy that a crisis in power supply is occurring incessantly in Delhi. It is just as a woman feels happy after the births of her child which makes her forget the labour pain. This is a pointed to the national leaders, a pointer to the whole country to ponder over. The time has come when they should think when the advanced planning of this country is based fundamentally on electricity, whether the Government has planned to make that amount of electricity available to the citizens as is required by them. We have been advancing the argument and have been trying towards the replacement of the steam locomotives by electric engines. We have been replacing the prime movers with electric movers and have been doing similar things as well. But all of a sudden we find that electricity itself is failing short, as if earth is going away from under our feet. We do not know how we will proceed with the work of planning important projects without electricity, given priority.

A cry came from West Bengal and Bihar. That reminds me of a story. A nurse was supervising the children's ward in the hospital. She found a child crying. The reason was not known to her. So many things were given to the child instead of milk, thinking that the child would keep quite and it will be all right and not knowing fully well why the child was crying and what it needed! Similarly, when the cry came from Bihar and West Bengal due to the power crisis, some jugglery was shown to them with charts and figures—*samjhota*—to keep them quiet. Unfortunately the cry there could not reach in a magnified way the ears of the people here who run the show of Government They could not be understood.

I would make this submission. Transformers are not generators. Transformers simply carry the energy and distribute it either by stepping up the voltage or stepping down the voltage. The point at issue is whether this Delhi Electric Supply Undertaking is actually in shortage of energy required for the consumer load. If the energy is ample, for this temporary stoppage of electrical energy on the ground that the transformer has gone wrong, the authorities have to be cen-

[Shri Priya Gupta]

sured much more, because it is only a question of getting it repaided or getting it replaced.

I would recall one aspect here. There was, in the British days, before we achieved Independence, an office called the Electrical Commissioner to the Government of India or something like that. That organisation went into the details of the instal.ed capacity of the generators in each power house all over India; it warned in advance, two years ahead sometimes, that the power will be shut down if the authority concerned does not attend to the power plant which needed attention, or if it did not replace the power units in time. They used to give advance notice. Whenever a load was given connection, whenever a licence was to be granted to a particular company, the first criterion was to see what the spare load was, what was the total consumer load, what was the plant load factor, what was the station load factor, what was the power factor and what was the peak load and when they required the peak load. Before giving power to the power-driven factories, etc., the criterion was whether or not the plant would meet the general domestic needs of the consumers.

When the workers in electricity concerns go on strike, the Government will just say, "You cannot strike; it is a public utility concern. You cannot strike work like this, then the hospitals will suffer." If it is such an important issue. There must have been cases where, owing to the failure of electricity in hospitals, in the operation room, the condition of people suffering from strangulated hernia, complicated labour cases etc. became serious. Owing to negligence of the Electric Supply Co. people concerned, havoc is created in operation rooms of hospitals. I do not mean the Willingdon Hospital but other smaller hospitals. I do not know what functions have been entrusted to the decentralised units of Electrical Commissioner's Office dealing with the electric supply—units which are now to take care of these things, to look into the details of the power plants, their condition and anticipated loads, the orders to be made and quantity to be supplied, replacement of the sets and other things.

Since I am the consumer, it does not mean that I should always remain at the sweet will of the company, whether it be a company run in the private sector or a company owned by the Government of India, depending upon the company for supply of electricity. Again, the companies cannot at their sweet will, stop the supply to the consumer. Though it may be an accident, it cannot take a very long period for rectification. The responsibility for such accidents should be fixed and the Electricity Act provides for it.

We have heard that there is *jagda* (dispute) between the Punjab Government and the Delhi Administration as to who will pay the electricity duty. A final decision could not be arrived at earlier as to what particular quantity of energy is to be made available to the DESU for supplying electricity to the consumers. We want to know why there has been this delay and why the Central Government—the Ministry of Irrigation and Power—did not intervene because it was a public utility service and give an early decision. If the rated capacity of the supplying plant was not in proportion, as required under the provisions of the law, why was the Government sitting idle? They must have checked up that if this is your consumer load, this must be your rated capacity installed in the power House and this must be your spare capacity. It is equally true of the generating plant and of the distributing plant, the transformer.

Without making any insinuation on them, I want to know whether the

purchase department, who procure transformers and other power units, were technically satisfied that this unit was quite all right and would serve our purpose. This is the only unfortunate chapter I can quote. In the railway administration also, we have seen many kinds of equipment which are purchased दो दिन के बाद निकम्मा and they become useless after sometime. After all, who is responsible for the purchase of these wrong things?

I have got nothing more to add except that the time has come when the Government, if it feels that the total generating capacity anticipated after the finalisation of the third and fourth Five Year Plans cannot be coped up by the present rated capacity or installed capacity of this country, taking all power houses—thermal, hydro-electric, oil, etc.—together, should find out as a first measure what steps should be taken in advance to cope with the portion of the capital, including the foreign exchange needed, to make good the deficiency in power for the third and fourth Plans.

This is not a thing to be looked over with ordinary consideration. This must be given serious consideration. I am happy—I repeat once again, I am happy—that this crisis happened under the nose of the Prime Minister and under the nose of the treasury benches. We forget our difficulties and our pain, but we are happy that it is a pointer to the administration that the time has come to ponder over the difficulties that we have to face if the power crisis is not removed.

Shri Ansar Harvani: Sir, never before in the history of this House perhaps there has been more unanimity in denouncing the administration for its inefficiency and incompetence than in dealing with the power crisis in Delhi. It has been a matter of shame for the entire nation, the way the entire problem has been tackled by the Ministry, by the Delhi Corporation and by the Delhi Electricity Supply Undertaking. It is a matter of same for all of us that in the capital of this country there has been continuous breakdown of power not only for the last few week, but for years and years, it has been repeating and we have done nothing to remove that.

In every country, specially in under-developed countries, the problem of electric power is the most important problem which has got to be tackled by the Government. In every country, especially in every under-developed country, the problem of electric power is handed over to the most dynamic hands, but in our country, it has been handed over to such hands about whose dynamism, I think my silence will be more eloquent than my speech and therefore, I am not referring to it.

There has been breakdown since October. They say that they have been trying to get transformers from here and there. But I have my own information that throughout the length and breadth of India, there are thousands of transformers which are lying idle. If the administration had the vision and the will to do it, they could have brought it from any part of the country. It is none of the concern of the electricity consumers of this conutry, it is none of the concern of the ordinary citizen of Delhi, from where the power is brought. It is none of the concern of the suffering humanity of the city of Delhi from where electricity has to be brought. It is the duty of the Government, it is the duty of the Ministry of Irrigation and Power to go from State to State, to beg, borrow or steal and provide electricity. I am really ashamed about the complacency of the Ministry of Irrigation and Power. They have been sitting silent over it.

You know it very well, Sir, that many years ago there was a plan to build up a thermal plant in Delhi. The shceme was approved and experts were brought. We are very fond of inviting experts from all over

[Shri Ansar Harvani]

the world. Sometimes Germans come, sometimes Italians come, sometimes Japanese come. Even Hungarians come here, who were much more backward than ourselves before freedom, and we depend upon then for building up our electric plant From time to time we keep on taking their advice. We give them our hospitality. But till today the thermal plant has not come into operation. I would like to know from the hon. Minister for Irrigation and Power why there is this delay. If that plant had been completed Delhi would not have had this catastrophe.

Sir, the time has come when this House, when the great Prime Minister of this country, who is very keen about electric power and who considers that the life-line of the country is electricity, should probe into the whole problem. The time has come when those people, from top to bottom, who are suspected or who are found to be responsible for this break-down, should be suspended. There should be no consideration of friendship; there should be no consideration of caste, there should be no consideration of community; there should be no consideration of religion. Anybody who is found responsible for this catastrophe should be sacked here and now. That is the message of this House to the Prime Minister.

Sir, much has been said by my hon friend, Shri Frank Anthony. Much has also been said by my hon. friend, Dr. K. L. Rao. Therefore, I do not want to take much time of the House. But, in conclusion, I would only appeal to the Prime Minister to pay his personal attention to all that has happened in Delhi, because this shows that if in the same way as the power crisis in Delhi has been tackled we tackle the problems in the whole of India, the future of India is doomed, the future of power in India is doomed, the future of our Plan is doomed.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली का महत्व अन्य शहरों की अपेक्षा कुछ विशेष है और इसलिये दिल्ली में जब इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो उन पर ध्यान भी विशेष रूप से दिया जाता है। सरदार पटेल जिस समय भारत के गृह मंत्री थे उस समय उनकी यह हार्दिक अभिलाषा थी कि दिल्ली में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई किसी क्षण भी उत्पन्न न हो और इसके लिये वह बराबर प्रयत्नशील भी रहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले दो, तीन वर्षों से राजधानी में तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। अभी शायद एक डेढ़ साल भी व्यतीत नहीं होता कि जब पानी की इसी प्रकार की कठिनाई दिल्ली में उत्पन्न हुई थी और इस सदन को अपनी कार्रवाई स्थगित कर उस पर विचार करना पड़ा था। आज फिर उसी प्रकार की एक समस्या इस सदन में विचार के लिये प्रस्तुत है कि दिल्ली में बिजली की कमी के कारण काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। मैं समझता हूं कि यह चेतावनी है न केवल राजधानी के नागरिकों के लिये अपितु सारे देश के लिये।

इस बिजली की कठिनाई के कारण जो आर्थिक हानि दिल्ली निवासियों को उठानी पड़ी है उसके मोटे मोटे आंकड़े जो मेरे पास अपनी जानकारी के सूत्रों के आधार पर उपलब्ध हो सके हैं वह मैं आपको देना चाहता हूं। दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग को अब तक १० लाख रुपयेकी हानि इस बिजली की कमी के कारण हो चुकी है। कारपोरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स लेती है उसको बिजली के अभाव में १ लाख २० हजार रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। अभी पीछे एक समाचारपत्र में यह प्रकाशित हुआ कि एअर कंडिशनर्स और रैफ्रीजिरेटर्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं और जिसमें कि २०० वाल्ट्स पावर की बिजली प्रयुक्त होनी चाहिये उसकी

मात्रा कम होने के कारण १६० वाल्ट्स बिजली ही मिल सकी जिसके कारण उनका कहना है कि २६ जुलाई तक २०० यंत्र इस प्रकार के खराब हो चुके हैं और जिन पर कि ५० रुपये से लेकर १००० रुपये तक उनके ठीक करने पर खर्च करना पड़ेगा ।

इसी तरह नजफगढ़ की एक बड़ी फैक्टरी के मालिकों ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि पावर फेलयोर से हमको करीब २००० रुपये प्रति घंटे की हानि है । ३० जुलाई को उस कम्पनी के मालिकों ने यह वक्तव्य दिया कि इस समय तक ५० घंटे की हानि हो चुकी है जिससे कि करीब १ लाख रुपये का नुक्सान यह इस समय तक उठा चुके हैं ।

इसी प्रकार दिल्ली फैक्टरी ग्रोनर्स असोसिएशन के प्रेसीडेंट श्री भास्कर ने भी अपना एक वक्तव्य दिया है । जो कोल्ड स्टोरेज दिल्ली मे हैं बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण उनमें लाखों रुपये के फल सड़ गये हैं । यह कुछ मोटे मोटे आंकड़े हैं जिनकी कि जानकारी उपलब्ध हो सकी है । लेकिन इनके अलावा और भी हानि लोगों को हुई है । फैक्टरी ग्रोनर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट ने कहा है कि हमने जो आर्डर्स ले रखे थे उनको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बिजली की सप्लाई समय पर उपलब्ध न हो सकने के कारण हम उनको पूरा नहीं कर सकते थे । मेरा अपना अनुमान है कि इन १५ दिनों में करीब १ या डेढ़ करोड़ रुपये की हानि दिल्ली शहर को आर्थिक दृष्टि से हुई ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की यह समस्या जो इस देश की राजधानी से सम्बन्ध रखती है और जिसके लिये विदेशों से स्पेयर पार्ट्स मंगाने के लिये लाइसेंस के लिये गवर्नमेंट को आवेदन-पत्र दिया गया । अभी कल-परसों की बात है कि दिल्ली कारपोरेशन में इसकी चर्चा आई और एक सदस्य ने कहा कि जब दिल्ली की एक प्राइवेट मिल को, जिसको इसी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स की जरूरत थी, पन्द्रह दिन में लाइसेंस मिल गया, तो यह क्या बात है कि इसके लिये लाइसेंस नहीं मिला । इसके उत्तर मे कारपोरेशन के मेयर साहब ने कहा कि यह सवाल तो पार्लियामेंट में पूछने का है, आप कारपोरेशन में हमसे सवाल क्यों पूछते हैं ? मैं चाहता हूं कि विद्युत मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में—अगर उनको इस एक वर्ष की अवधि में जानकारी प्राप्त हो चुकी हो—कृपया इस स्थिति का स्पष्टीकरण करें कि क्यों इस विषय में लाइसेंस मिलने में देर हुई, जिसके कारण दिल्ली के नागरिकों को इस प्रकार की हानि का सामना करना पड़ा ।

इस विषय में एक प्रश्न यह भी सामने आता है कि जब इस प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें बाहर से मंगाई जाती हैं और एक छोटा सा पुर्जा खराब होने की वजह से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है, तो क्यों नहीं मशीन खरीदते समय ही उसके लिये स्पेयर पार्ट्स और अधिक ले लिये जायें, ताकि अगर कभी ऐसी कठिनाई में फंसना पड़े जैसी आज है तो उस समय उनको इस्तेमाल किया जा सके ।

प्रायः यह देखा गया है कि ट्रांसफार्मर की आयु पैंतीस वर्ष के लगभग होती है लेकिन यह ट्रांसफार्मर सात आठ वर्ष में ही खराब हो गया । क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि जब सात आठ वर्ष में ही यह ट्रांसफार्मर अपनी आयु समाप्त कर बैठा, तो जिनसे ये सफार्मर खरीदे गये थे, क्या उनसे कोई गारण्टी ली गई थी यदि कोई गारण्टी ली गई थी, तो क्या सरकार के साथ इस प्रकार का धोखा त नहीं हुआ कि नये ट्रांस-फार्मर के नाम पर पुराने ट्रांसफार्म खरीद लिये गये और उन पर देश का पैसा बर्बाद किया गया ? ये तमाम बातें इस समस्या के सम्बन्ध में सामने आती हैं और मस्तिष्क में प्रश्न उत्पन्न करती हैं ।

लेकिन मैं आप के द्वारा सदन को इस से भी बड़ी दुखभरी जानकारी देना चाहता हूं ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री

अभी कल-परसों विद्युत् मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया कि पंजाब से हम को जो बिजली लेनी पड़ती है, उस के अतिरिक्त दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग यहां पर ४५,८०० किलोवाट बिजली तैयार करती है। लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो डीज़ल से चलने वाले जेनीरेटर हैं, उन को भी कुछ स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है। उन्होंने लाइसेन्स के लिए एप्लाई किया है, लेकिन अभी तक उन को भी लाइसेन्स नहीं मिल पाये हैं, जिस का परिणाम यह हो रहा है कि उन पुर्जों के अभाव में वे जेनीरेटर केवल तेरह हज़ार किलोवाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जब कि वह बीस हज़ार किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सिर्फ़ रोहतकरोड के ट्रांसफ़ार्मर की समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या दूसरे जेनीरेटरों के साथ भी है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसी तमाम स्थितियों का सामना करने के लिए एकसामान्य नीति बना कर उस के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं है।

विद्युत मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में सदन को वह आश्वासन दिया था कि कल से बिजली बन्द रहने के घंटों में कमी होना शुरू हो जायगा, लेकिन उस के एक दिन बाद यानी ८ अगस्त को बिजली बन्द रहने के घंटों में वृद्धि हो गई। कल पटेलनगर में साढ़े चार घंटे बिजली बन्द रही और मालीवाड़ा में छ: घंटे बिजली बन्द रही। माननीय मंत्री सदन को आश्वासन देते हैं कि बिजली बन्द होने के घंटों में कमी होती चली जायगी, लेकिन उन की और बढ़ोतरी होती चली जा रही है।

मैं आप के द्वारा सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि जिस समय भारत सरकार ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे, तो पंजाब सरकार ने कहा कि चूंकि वह ट्रांसफ़ार्मर उन के एरिया में पड़ता है, इस लिए भारत सरकार द्वारा जांच कराये जाने पर हमारी मान-हानि होगी और इस लिए हम स्वयं इस सम्बन्ध में जांच करेंगे। पंजाब सरकार ने जांच का आश्वासन तो दिया, लेकिन उस ने जो टर्म्ज़ आफ़ रेफ़रेंस तय किये हैं, उन में इतना तो है कि इस बात की जांच की जायगी कि वह ट्रांसफ़ार्मर कैसे जला, लेकिन उस के लिए ज़िम्मेदार कौन है, इस के सम्बन्ध में कोई मुद्दा उस में तय नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि इस की ज़िम्मेदारी किस की है, जिस की ग़लती की वजह से इतनी बड़ी हानि का सामना करना पड़ा।

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि आख़िर केन्द्रीय सरकार देहली राजधानी को भाखरा-नंगल की बिजली पर कब तक निर्भर रखेगी। जैसी भूमिकायें आज देश में तैयार होने लगी हैं, जिस प्रकार आज केन्द्र और राज्यों में खिचाव शुरू हो गया है, उन को दृष्टि में रखते हुए भविष्य में किसी समय ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि पंजाब राज्य देहली को बिजली देना बन्द कर दे। उस समय राजधानी के सामने नये सिरे से समस्या उत्पन्न होगी। क्यों न केन्द्रीय सरकार अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ऐसी व्यवस्था करे कि वह बिजली के विषय में स्वावलम्बी स्थिति में हो जाये?

जो यह घटना घटी है, उस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यह कहती है कि कार्पोरेशन ज़िम्मेदार है और कार्पोरेशन कहती है कि पंजाब गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। आज आपस में जो यह ताल-मेल नहीं बैठ रहा है, यह अवस्था कब तक जारी रहेगी? आख़िर कब तक एक दूसरे पर आज ज़िम्मेदारी टालने की कोशिश की जाती रहेगी? इस लिए आवश्यकता इस बात की भी है कि एक हाई-पावर बोर्ड बनाया जाये, जो दिल्ली की विद्युत समस्या को अपने तौर

पर हल करे और किसी पर उस को निर्भर न करना पड़े ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रायः यह देखा गया है कि जब इस प्रकार की घटनायें होती हैं, तो जांच कमीशन बैठा दिये जाते हैं । जांच कमीशन महीनों तक जांच करते हैं और उस पर लाखों रुपये व्यय होते हैं और अन्त में परिणाम यह होता है कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया" । कह दिया जाता है कि चपरासी का कुसूर था अथवा इंजीनियर अपने समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था, इसलिए ट्रांसफ़ार्मर जल गया । ढिलवां में हमारे पौने दो करोड़ रुपये के स्लीपर जल गये, लेकिन जांच के परिणामस्वरूप एक चपरासी को बरखास्त कर दिया गया । हम देखते हैं कि बड़े बड़े रेल के एक्सिडेंट होते हैं और उन के बारे में कह दिया जाता है कि सिग्नल ठीक नहीं दिया गया था । मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट को आज यह तय करना चाहिए कि जो इस प्रकार की भयंकर दुर्घटनायें होती हैं, जो कि सारे देश के लिए चुनौती होती हैं, उन की ज़िम्मेदारी केवल इंजीनियरों और आफ़िसरों पर न डाली जाये बल्कि अब वह समय आ गया है कि मिनिस्टरों को भी इस ज़िम्मेदारी से मुक्त न किया जाय और उन पर भी ज़िम्मेदारी डाली जानी चाहिए, और उन से भी जवाब तलब किये जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की बिजली समस्या के बारे में मेरे दूसरे मित्रों ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं उन से सहमत हूं । अभी ६ अगस्त को हिन्दुस्तान टाइम्ज़ के एडिटोरियल में, जिस का शीर्षक था "कैपिटल शेम", यह लिखा था कि अगर इस प्रकार की स्थिति किसी दूसरी जगह होती, तो लोग विरोध की भावना प्रकट कर के न रह जाते, बल्कि वे इस बात की मांग करते कि मंत्रि-मंडल को चाहिए कि वह इस्तीफ़ा दे दे ।

मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब दिल्ली में पानी की कमी हुई, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तड़प तड़प कर बेहाल हो रहे थे, तो इसी सदन में यह विश्वास दिलाया गया था, खास कर हमारे प्रधान मंत्री जी की तरफ़ से, कि ऐसी हालत फिर नहीं होगी । उस वक्त कहा गया कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं था कि जमनाजी अपना रुख बदल रही है और उन को कम से कम दस साल के बाद अचानक मालूम हुआ कि जमना जी अब अपना रुख बदल रही है और उस रुख को ठीक करने के लिए बाद में एक कमीशन का निर्माण हुआ । मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश में कमीशन बैठता है, बैठने के बाद लेटता है और लेटने के बाद सो जाता है और उस को जगाने के लिए एक आन्दोलन करना पड़ता है । इस लिए मैं समझता हूं कि यह देखते हुए कि ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर थोपी जा रही है, पंजाब सरकार यह कहती है कि इस मामले की जांच हम करेंगे और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ज़िम्मेदारी को टालना चाहती है, जुडिशल एन्क्वायरी की मांग बिल्कुल ठीक और मुनासिब है ।

मेरे एक मित्र ने हंसते हुए मुझ से पूछा कि आखिर बिजली का यह संकट क्यों पैदा हुआ है, तो मैं ने भी हंसते हुए कहा कि मालूम होता है कि हमारी पावरफुल सरकार शायद पावरलैस होती जा रही है, या ऐसा है कि शायद पावर-ड्रंक सरकार दूसरे को पावर सप्लाई करने में असमर्थ है । मैं समझता हूं कि इस के बारे में पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए ।

ट्रांसफ़ार्मर जल चुका पिछले अक्तूबर में और उस के लिए स्पेयर पार्ट्स के इम्पोर्ट लाइसेन्स की मंजूरी दी गई जुलाई में । हम देखते हैं कि जब किसी मामूली सरमायादार को इम्पोर्ट लाइसेन्स की जरूरत होती है, तो किसी अंडर सैक्रेटरी या डिप्टी सैक्रेटरी से

[श्री स० मो० बनर्जी]

बात न कर के वह मंत्री महोदय के पास जा कर ला सकता है, लेकिन जहां पर लोगों की रोज़-मर्रा की ज़िन्दगी का सवाल है, तो इम्पोर्ट लाइसेन्स मिलने में इतनी दिक्कत बताई जा रही है। इस बात का सवाल नहीं है कि आज लोगों को फ़ैन की आदत हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि विद्यार्थियों का क्या होगा। मैं खुद जानता हूं कि पांच बजे जाने के बाद जब सात बजे हमारे स्टेनोग्राफ़र आते हैं, तो मालूम होता है कि बिजली चली गई और उस के बाद वह आठ या नौ बजे आती है। मैं समझता हूं कि नार्थ ऐवेन्यू और साउथ ऐवेन्यू के लोग भाग्यवान् हैं, क्योंकि वे पार्लियामेंट के सदस्य हैं, इस लिए वहां पर बिजली थोड़ी देर के लिए जाती है, सिर्फ घंटे भर की तक्लीफ होती है। (*Interruptions*). घंटे दो घंटे बिजली बन्द रहती है।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): Four hours daily.

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा होगा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, दोपहर को एक घंटा और शाम को एक घंटा बिजली बन्द रहती है। (*Interruptions*). लेकिन दूसरे इलाकों में, जहां पार्लियामेंट के मेम्बर नहीं रहते हैं, आप जा कर देखें, तो वहां के लोग कहेंगे कि घंटों का कुछ हिसाब ही नहीं है। लोग कहते हैं कि चूंकि यह बड़ा सीरियस क्राइसिस है, इस वजह से छः घंटे कुछ नहीं हैं, हमें तो सरकार को बधाई देनी चाहिए कि हमेशा के लिए, बिजली बन्द नहीं की जाती है। यह उन को तसकीन दी जाती है, वह उनको तसल्ली दी जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सिर्फ ज्यूडीशल इनक्वायरी का सवाल नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर यह मसला हल नहीं हुआ, अगर इसकी जिम्मेवारी ठीक तौर से उन पर नहीं डाली गई जोकि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले हैं तो बहुत ही खराब बात होगी। और भी जगह देश में इस तरह के वाकात हुए हैं। डी० वी० सी० में इस तरह से फेल्योर हुआ था और उस वक्त मैं कलकत्ता में था। इसके फेल होने से कैसी जिन्दगी वहां पर लोगों की हो गई यह मैं यहां बयान करना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि अगर अच्छी तरह से इसको देखा जाये तो आप इस नतीजे पर पहुंचे बिना नहीं रह सकेंगे कि जो लोग इंचार्ज हैं, उन को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिये। लेकिन मुझे खतरा यह मालूम देता है कि जिस तरह से ट्रेन दुर्घटनाओं पर बहस हुई थी, उसके बाद से जिस तरह से दुर्घटनायें बढ़ने लग गई थीं, उसी तरह से इस बहस के बाद भी कहीं ऐसा न हो कि जहां आज दो घंटे या तीन घंटे के लिए बिजली जाती है, वहां वह चार घंटे के लिए जाने लग जाये। अकसर बहसों का ऐसा ही नतीजा निकला करता है।

17 hrs.

जो अफसर होते हैं वे समझते हैं कि जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो जो ब्रीफ उन्हों ने मिनिस्टर्ज को दिया है, उसको वे पढ़ेंगे और बाद में जब मिनिस्टर साहब बाहर आयेंगे तो उन को बधाई दे देंगे और कह देंगे कि आप ने हमारी जान बचा ली है। लेकिन उस के बाद जो होता है वह हम ही जानते हैं। दे ट्रीट अस विद वैंजीऐंस। उस के बाद वे समझते हैं कि पावर क्रासिस और डिवलेप हो।

मैं रूलिंग पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में जो एक क्रासिस हो रहा है, वह कम से कम देश भर में तो आप पैदा न होने दें और अगर एसा होता है तो यह बड़ी खराब बात होगी। क्रासिस रिडन देश चल नहीं सकता है। आप रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन करने जा रहे हैं। जो हालत बिजली की आज है अगर वह तब हुई तो बहुत बुरा होगा। मैं चाहता हूं कि आज की डिसकशन को सिर्फ बहस न समझा जाए, बल्कि नो-कान्फिडेंस या सेंशर समझा जाय। आज की परिस्थिति में आप को चाहिये कि उन लोगों को आप ससपेंड करें

जो इस के लिये जिम्मेदार हैं। ऐसा न हो कि बाद में आप को अचानक मालूम हो जाय कि एक और चूहा घुस गया था इसलिये ट्रांसफार्मज जल गया और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयीं। मैं चाहता हूं कि हाई पावर्ड कमीशन नहीं बल्कि जुडीशल इन्क्वायरी हो ताकि लोग जा कर वहां गवाही दे सकें।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहिम) : जनाब स्पीकर साहब, इस से पहले कि जो बहस यहां हुई है उस के बारे में कुछ अर्ज करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हर साल जमना में पानी खुश्क होता रहता है। वकतन फवक्तन ऐसा होता रहता है। इस के नतीजे के तौर पर ऐसा भी वक्त आता है जब वह ज्यादा खुश्क हो जाता है और पावर हाउस को चलाने के लिये जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी नहीं मिलता और उतनी जैनरेशन हो नहीं सकती। आज अगर इस तरह की चीज पैदा हो तो उस के लिये यह इंतजाम हो गया है कि उत्तर प्रदेश के इंजीनियर जो ओखला में रहते हैं, उन्हों ने कह दिया है कि हम उस जगह को साफ कर के और पानी को रवां कर देंगे और दिक्कत वाका नहीं होगी और ऐसा नहीं होगा कि इस किस्म की तकलीफ हो।

जहां तक इस मुवाहिसे का ताल्लुक है, मैं उन सब मैम्बर्ज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्हों ने इस में हिस्सा लिया है। मैं समझता हूं कि इस से मुझ को और मेरे उन साथियों को जो इस काम को करते हैं, बड़ा सबक हासिल करने का मौका मिला है। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आप ने जो सबक दिया है, उस को याद रखें और जो बातें आप ने कहीं हैं उन पर अमल करें। मैं समझता हूं कि बहस में कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो गलतफहमी पर मबनी थीं। मैं मानता हूं कि कुछ बातें ऐसी भी कही गई हैं जो सही थीं। मगर उन के साथ साथ कुछ ऐसी भी कह दी गई हैं जो गलतफहमी पर मबनी थीं।

श्री भागवत झा आजाद : जैसे ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अभी उन पर आता हूं, सब्र रखिये।

जितनी भी तकरीरें मैंने सुनी हैं, उनमें से एक बात निकलती है। मैम्बर साहिबान की तरफ से कहा गया है कि यह दिल्ली वालों की करतूत है हालांकि उन की यह बिल्कुल भी करतूत नहीं है, कतई भी नहीं है। मैं एक दूकान से चीज खरीदता हूं और दूकानदार मुझ को देता है और मेरे घर पहुंचते ही या रास्ते में अगर वह चीज खराब हो जाती तो यह किस की जिम्मेदारी होगी ? इस बात का फैसला करना मुश्किल नहीं होना चाहिये। यही पोजीशन हमारी है। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी बिजली यहां इस्तेमाल होती है उस में से आधी बिजली तो भाखड़ा नंगल से आती है। वह पंजाब गवर्नमेंट का है....

Shri Hanumanthaiya: Since some of us are not able to follow the language of the hon. Minister, may I request him to speak in English? (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order. It is for the hon. Minister to choose any language that he likes.

Hafiz Mohammed Ibrahim: I am very sorry. I would have started in English, but I have already started in Hindi, and, therefore, I request my hon. friends to allow me to continue and to finish my speech in Hindi. I am sorry that I cannot act on the advice of my hon. friend at the present moment.

मैं अर्ज कर रहा था कि वह बिजली भाखड़ा में बनती है और वहां से ट्रांसमिशन लाइंज से यहां तक आती है। ट्रांसमिशन लाइन्ज भाखड़ा की हैं। जितने उन में कल पुर्जे लगे हुए हैं वे सब पंजाब के हैं। पंजाब उन का मालिक है, उसी ने उन को लगाया है, उसी ने उन को खरीदा है और जो इंजीनियर हैं, वे भी उन्हीं के हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : आप ने जो रुपया दिया है उस का क्या हुआ ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : इस के साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मज खराब हुआ है, वह भी उन्हीं का है । यहां पर दिल्ली में जो लोग काम करते हैं, उन का उस से कोई ताल्लुक नहीं है । इन हालात में मैं कैसे कह सकता हूं कि दिल्ली में जो काम करने वाले हैं, उन्हों ने किसी किस्म की खराबी की है । किस तरह से मैं उन पर किसी किस्म का इलजाम लगा सकता हूं और कैसे कह सकता हूं कि वे इल्जाम के काबिल हैं । मैं समझता हूं कि उन के ऊपर उस का इलजाम नहीं है । उन्हें तो यही देखना है कि पंजाब के उस ट्रांसफार्मर को क्या हुआ ।

अभी आपने सुना कि ट्रांसफार्मर सात साल हुए खरीदा गया था और ट्रांसफार्मर की उम्र ३५ बरस या ३८ बरस की होती है । वाका ऐसा हुआ है कि वह सात बरस के अन्दर ही खराब हो गया । क्यों खराब हुआ, इस को आज कोई शख्स नहीं बता सकता है । यह टैक्नीकल चीज है और टैक्नीकल आदमी ही इस की वजह बता सकता है । टैक्नीकल आदमी जो बुला लीजिये और वह जब तक पूरी तहकीका नहीं कर लेगा, पक्के तौर पर उस वक्त तक कतईन नहीं कह सकेगा कि क्या बात हुई और इस का क्या काज रहा अब उस के लिये कमेटी बिठाई गई है ।

अब जहां तक कमेटी बिठाने का ताल्लुक है वह काम भी उन्हीं का था, पंजाब गवर्नमेंट का था । उन्होंने बह कमेटी बिठा दी है और यह काम उस के सुपुर्द कर दिया है कि वह बताये कि इस का क्या सबब था, कैसे यह खराबी हुई । अब इस खराबी के बारे में कमेटी रिपोर्ट देगी और मालूम हो जायगा कि क्या वजह हुई और कौन जिम्मेवार है ।

जहां तक बिजली की शैडिंग का ताल्लुक है, यह ठीक है कि लोगों को तकलीफ हो रही है और यह भी ठीक है कि तीन तीन घंटे बिजली बन्द रहती है, चार चार घंटे बन्द रहती है । इस की निसबत मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो कटौती हुई है यह बीस तारीख से बिल्कुल खत्म हो जायेगी, ऐसी तवक्कय की जाती है । ट्रांसफार्मर भी लग जायेगा और मौजूदा तकलीफ भी दूर कर दी जायेगी । अब सवाल पैदा होता है कि हमारी ख्वाहिश के खिलाफ ऐसा क्यों हुआ ? दुनिया में हमारी ख्वाहिश के खिलाफ कोई भी बात न हो, वह मुम्किन नहीं है । हां यह बात दुरुस्त है कि हम जान बूझ कर करें तो हम उस के गुनाहगार हैं । लेकिन कुछ बातें होती हैं, कुछ तकलीफ इंसान पर आती है, जिन को उस को भुगतना पड़ता है । उस तकलीफ की वजह से मैं किसी पर गलत इलज़ाम लगा दूं, वह कैसे हो सकता है और न ही यह बात मेरी समझ में आती है । किसी पर भी ख्वाह-म-ख्वाह इलज़ाम नहीं लगाया जा सकता है । अगर इस का इलज़ाम आ सकता है तो पंजाब पर ही आ सकता है

एक माननीय सदस्य : पंजाब हिन्दुस्तान में है या बाहर ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : पंजाब हिन्दुस्तान में है, इस को मैं मानता हूं । चूंकि यू० पी० भी हिन्दुस्तान में है, मद्रास भी है, पंजाब भी है, सभी सूबे हैं, तो क्या उस का मतलब यह है कि एक सूबे का आदमी अगर गुनाह करता है, तो मैं कह दूं कि उस के कान पकड़ लो? जहां का आदमी जो कुसूर करे वह उस की सजा पायेगा । क्या इस के यह माने हैं कि हिन्दुस्तान जो है उस के अन्दर से आदमियत बिल्कुल निकल गई है ? आदमी रहते हैं, जगह जगह पर, और वे काम करते हैं । उन से गलती भी होती है, सही बात भी होती है । इस से वह नतीजे निकालने जोकि यहां निकाले जा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है । यह तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं है जिस के लिये यह समझा जाय कि और कुछ होना चाहिये । इस के लिये यही हो सकता था,

श्रौर जो कुछ इस के लिये होना चाहिये था वह हो गया है । कमेटी बनाई गई है, वह मालूम करेगी ।

इस के बाद में अर्ज कर दूं . .

Shri S. M. Banerjee: On a point of order. Many hon. Members, from this side as well as from the other, have demanded a judicial inquiry and so on. But in the speech of the hon. Minister, he says:

'इल्जाम किस पर है श्रौर किस पर नहीं है'

This clearly means that this is no inquiry but just an eye-wash. I would only request the hon. Minister not to say such things or use these words. Otherwise, there will be no inquiry worth the name.

Mr. Speaker: Is he now satisfied that he has made out a point of order?

Shri S. M. Banerjee: No, Sir. My point of order is only this, whether the Minister should use these words, casting doubts on the genuineness of the inquiry.

Mr. Speaker: The hon. Minister might proceed.

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जुडिशल एन्क्वायरी श्रौर एन्क्वायरी बाई एग्जिक्यूटिव यह दो चीज तो हैं, लेकिन इस बात में तमीज करनी होती है कि किस मौके पर श्रौर किस लिहाज से जुडिशल एन्क्वायरी होनी चाहिये श्रौर किस मौके पर एग्जिक्यूटिव के जरिये से एन्क्वायरी होनी चाहिये । कोई जुडिशल प्राब्लेम इस के अन्दर नहीं है । कोई चीज फलां से टूट गई, इस के लिये सुप्रीम कोर्ट का जज बलाया जा, वह श्रा कर तहकीकात करे कि यह कैसे टूट गई, यह कैसे हो सकता है? हुजूर वाला, हिन्दी का एक मसला है :

"जिस का काम उसी को साजे" । दूसरा हिस्सा क्या है ? मुझे वह याद नहीं रहा । बहरहाल जो चीज जिस के काबिल होती है उसी से कराई जानी चाहिये । इसलिये यह काम कमेटी के सुपुर्द किया गया । अब उन को बेईमान हम समझें, उन पर ऐतबार न करें, अगर इस तरह से होता है, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में किसी मौके पर किसी के ऊपर ऐतबार नहीं किया जा सकता । सारी सर्विसेज को ही खराब समझ लिया गया है । साहब, बेऐतबारी तो उस के मुताल्लिक हो सकती है जिस के मुताल्लिक बेऐतबारी साबित हो गई हो । आप ने बेईमानी देखी तो है नहीं, लेकिन सोचते हैं कि चूंकि आदमी है इसलिये बेईमानी करेगा ही । पहले से यह तय कर लिया गया है कि आदमी है, बेईमानी जरूर करेगा । इस प्रिजम्शन के ऊपर कि चूंकि आदमी है इसलिये बेईमानी करेगा जरूर, उस में बेईमानी करने का माद्दा है जरूर, यह गलत है । यह चीज नहीं चल सकती ।

श्री त्यागी : उसे तो बिजली ने जलाया है । वह बिजली की गर्मी से जला है, किसी आदमी ने नहीं जलाया ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : आप खुद अपनी बात फरमाते हैं, मुझे आगे नहीं चलने देते । इस तरह से कैसे काम चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब को आगे चलने दिया जाये . .

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : लोड शेडिंग के बारे में मैं ने अर्ज कर दिया कि वह गड़बड़ी २० तारीख तक खत्म हो जायेगी । *(Interruptions)*.

इस से पहले जो ट्रांस्फार्मर खराब हुआ उस की बाबत मैं अर्ज नहीं करना चाहता । लेकिन उस की निस्बत मैं ने यही लोगों को फरमाते सुना कि फलां वक्त हुआ था श्रौर इतने अर्से के बाद उस का लाइसेंस दिया गया । बात तो यह सही है श्रौर वक्त होता तो मैं उस के बारे में बतलाता । उस की कुछ तफसील है मेरे

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

पास । वह सब मैं आप को दिखा देता । उस से आप को मालूम हो जाता कि यहां की किसी मिनिस्ट्री का उस में कोई कुसूर नहीं है । जहां तक उस की एजेन्सी का वास्ता है, उस एजेन्सी की निस्बत भी उन तहरीरों में जो यहां हैं, कोई बात लिखी हुई नहीं है और न किसी से उस में देर हुई है । अगर कोई बात हुई तो उन्हीं से हुई । पंजाब वालों का ही ट्रांस्फार्मर था और उसी लाइन में सब कुछ हुआ जो यहां भाखरा की बिजली को ला रहा है । जो भी खराबी थी वह वहीं पर हुई । यहां सेन्टर में किसी से कोई खराबी नहीं हुई ।

श्री त्यागी : एक ऐतिराज यह किया गया है कि इम्पोर्ट लाइसेंस मंजूर करने में आप की गवर्नमेंट ने देर की है । इस का क्या जवाब है ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जूर वाला, नहीं की है ।

श्री त्यागी : यानी देर नहीं की है ? जिस दिन एप्लाई किया उसी दिन मिल गया ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : हां, महीने दो महीने हमने नहीं लगाये । (*Interruptions*).

श्री शं० शा० मोरे (पूना) : पंजाब गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन करने में देर लगा दी ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : यह बात भी है । इस में यह तक नहीं लिखा है कि . . . . . (*Interruptions*).

श्री गौरी शंकर (फतेहपुर) : मुझे यह अर्ज करना है कि यह जो घरेलू बातें होती हैं उस से कुछ सुनाई नहीं देता ।

अध्यक्ष महोदय : इसी लिए मैं ख्याल कर रहा हूं कि मैं चला जाऊं यहां से ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : हर जगह जिम्मेदारी का जिक्र है यहां, जिम्मेदारी का, रिस्पांसिबिलिटी का, और कुछ मेरे दोस्तों का ख्याल यह है कि शायद सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है इरिगेशन ऐंड पावर की, वह इस के लिए जिम्मेदार है । मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूं, हुजूर से, कि बदकिस्मती से . . . .

अध्यक्ष महोदय : हाफ़िज़ साहब तो बुज़ुर्ग हैं, हाथ तो मैं जोड़ता हूं । वह क्यों जोड़ें ? यहां डिमोक्रेसी में न कोई हुजूर है और न किसी को हाथ जोड़ना चाहिये ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारयण सिंह) : यह "सर" का ट्रांस्लेशन है ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : यह तो हमारे हिन्दुस्तान की तहज़ीब की बहुत पुरानी चीज है जो कि बुज़ुर्गों से चली आई है और हमारे तमाम जिस्म में छाई हुई है । मैं ने उसी में परवरिश पाई है । यह कोई बदतमीज़ी नहीं है, किसी के खिलाफ़ कोई बात नहीं है, बल्कि अदब है, रिस्पैक्ट है जो एक आदमी अदा करता है बड़े आदमी को । वह साइन है, एक्स्प्रेशन है बाहर की दुनियां की तरफ़, जिस में दुनियां समझती है कि उसने अदब से बात की है इस में ऐसी कोई बात नहीं है जिस के लिए समझा जाये कि वह गलत है, अगर मैं उनको ऐड्रेस करता हूं "हुजूर" कह कर । आज कल तो लोगों ने हुजूर के लफ्ज को छोड़ना शुरू कर दिया है । मैं इस से वाकिफ़ हूं । लेकिन मैं तो ६०, ६५ बरस का आदमी हूं और मैं ने तालीम पाई थी इस बात की ।

Shri Frank Anthony: Before this dissolves itself into a farce, may I ask, with your permission, two questions? When did the Centre come in when the breakdown occurred? Why did not the Centre take steps to get a transformer, to import it? Secondly, why are we still undergoing chaotic conditions? Every day there is a

change with regard to the scheduled and unscheduled cuts. Please reply to these two matters.

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं समझता हूं कि जो साहिबान बिजली इस्तैमाल करते हैं उनको इस किस्म के तजरुबे हुए होंगे और वह इस बात को समझ लेंगे ।

जहां तक शेडिंग का सवाल है, जिस हिस्से मे शेडिंग होता है उसमें जितना लोड होना चाहिए उससे लोग ज्यादा लोड ले लेते हैं । जो वहां के बिजली इस्तैमाल करने वाले हैं वे ज्यादा बिजली ले लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब मेरी तरफ़ मुखातिब हों तो ज्यादा बेहतर होगा । उन्होंने दो सवाल किये हैं । एक तो यह कि सेंटर इस वक्त आया और दखल देने लगा, तो पहले सेंटर ने दखल क्यों नहीं दिया । और दूसरा सवाल यह था कि जब शेडिंग का शिड्यूल बनाया जाता है तो उसके मुताबिक़ शेडिंग क्यों नहीं किया जाता । जो वक्त बतलाया जाता है उससे दूसरे वक्त में बिजली बन्द कर दी जाती है जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है । ये सवाल एंथनी साहब ने किये हैं ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं समझता हूं कि मैं लेजिस्लेचर में बोल रहा हूं और वह भी हिन्दुस्तान के लेजिस्लेचर में बोल रहा हूं जहां इस बात को गालिबन साफ़ कहने की जरूरत नहीं है । यहां सब ने कांस्टीट्यूशन को देखा है और उसको अच्छे तरीक़े से जानते हैं । इलेक्ट्रिसिटी स्टेट्स का सबजेक्ट है और प्रेक्टिकली तमाम स्टेट्स इस मामले में आजाद हैं । जहां तक सेंटर का ताल्लुक है उससे किसी स्टेट के ऊपर किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा होती ।

Shri Priya Gupta: On a point of order, Sir. The Indian Electricity Act and Rules have got provisions that the Centre can intervene in such cases of breakdown as it is covered under the provisions of the Law of the Land. So, under that it is a Central subject now.

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं अर्ज करूं कि जो वह फरमाते हैं वह कहीं नहीं लिखा है । लेकिन लिखा न होने के बावजद हम इंटरवीन करते हैं, वह एक अलग बात है । मैं तो इस वक्त यह अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक कांस्टीट्यूशनल और लीगल जिम्मेदारी का सवाल है वह मेरी नहीं है । मुझे तो कोई अख्तियार नहीं है । मैं उसके अन्दर दखल नहीं दे सकता । मैं उनके साथ मुहब्बत से, इखलाक़ से बरताव करता हूं, तो वह मेरी बात सुनते हैं । यह अगल बात है। लेकिन जहां तक कानूनी जिम्मेदारी का सवाल है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता ।

दिल्ली के बारे में बजली का जो कानून हैं वह मेरे पास है । उसको मेरे दोस्त देख लें । यह काम कारपोरेशन के जिम्मे है । उसने इसके लिए एक कमेटी बनायी है और उस कमेटी के लिए साफ साफ लिखा है इस कानून में जोकि उसको क्या क्या करना हैं और क्या क्या नहीं करना हैं । मैं इन मामलों में जो जवाब देता हूं उसकी एक वजह हैं । जब पंत जी के पास होम मिनिस्ट्री थी तो उनकी यह राय थी कि दिल्ली की बिजली के बारे में जो सवालात हों उनका जवाब मेरी मिनिस्ट्री दे दिया करे । इस बिना पर हमारी तरफ़ से जवाब दिए जाते हैं वरना मुझे मिनिस्टर की हैसियत से यहां की बिजली से कोई वास्ता नहीं है । मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता । लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि मुझ से जो कुछ हो सकता है वह मैं न करूं । मैं तो वह कर ही रहा हूं इस मामले में भी और आगे भी जो मामले आएंगे उनमें भी करता रहूंगा । लेकिन वह दूसरी बात है । लेकिन यहां कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जिन आदमियों की यह कांस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी है उस को वे पूरा नहीं कर रहे हैं । यह बात गलत है और इसी लिए मुझ को यह बताना पड़ा कि यह मामला पंजाब का है और

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

दिल्ली को इस से कोई वास्ता नहीं । हां इससे लोगों को जो तकलीफ़ हुईउससे हर इन्सान को तकलीफ़ होगी । लेकिन ऐसा किसी ऐसे आदमी के कुसूर से नहीं हुआ जिसकी जिम्मेदारी थी और उसको उसने पूरा नहीं किया । मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, उसको दुहराने की जरूरत नहीं है ।

Shri N. Sreekantan Nair (Quilon): Is it in order for a Minister to give his entire reply in Hindi when there are members like me who do not understand a word of Hindi. I would like to know whether I would be given at least a summary or not.

Some Hon. Members: No, no.

Shri Hanumanthaiya: When other Members who know Hindi become intolerant towards some of us, who for no fault of ours do not know Hindi, is it the proper psychology to encourage Rashtra Bhasha? I protest against this psychology of many of my hon. friends who say: no, no, whenever an hon. Member really and sincerely wants to understand what the hon. Minister says. It this the way of receiving and accommodating all the people of India and integrating them?.... (*Interruptions.*)

Hafiz Mohammad Ibrahim: Unfortunately, the position is that there are so many also in this House who do not understand English at all.

Mr. Speaker: After the hon. Minister has completed his reply in Hindi he may give a gist of it in English also.

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : मिनिस्टर साहब जरा जोर से बोले ताकि जो हिन्दी समझ सकते हैं वह तो समझ लें । मैं जहां बैठी थी वहां से कुछ सुन नहीं सकती थी । लेकिन यहां आने पर भी समझने में तकलीफ़ होती है । वह जरा जोर से बोलें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हाफ़िज साहब से दरखास्त करूंगा कि वह अपना बयान बजाए बाएं के दाएं करें । या मैं मिनिस्टर फार पार्लियामेंट एफ़ेयर्स से दरखास्त करूंगा कि वह दाएं को चले जाएं ।

Hafiz Mohammad Ibrahim: I was saying that as far as responsibility for electricity is concerned, the Centre has no responsibility. This probably is known to the Members of Parliamene or of the assemblies.... (*Interruptions.*) as far as Delhi is concerned, according to the law that has been made electricty has been entrusted and given to the Corporation which has formed a committee for that purpose, which runs the whole thing. Personally, as a Minister I have nothing to do. Under a private arrangement it was settled that as far as parliamentary questions are concerned, the Irrigation and Power Ministry may give the replies to the questions and nothing more.... (*An Hon. Member: Then why discuss it here?*) That is the position as far as Delhi is concerned.

Shri Frank Anthony: It is not a fact that electricity is in the Concurrent List?

Hafiz Mohammad Ibrahim: Yes. What does it mean? He may discuss that with me separately. If he wants to discuss it he must first explain what he understands from the word 'concurrent'. I will explain it.

Mr. Speaker: Is the speech concluded.

Hafiz Mohammad Ibrahim: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Then the House stands adjourned.

17.30 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 10, 1962/*Sravana* 19, 1884 (*Saka*).